कमल संदेश
ikf{kd if=dk

संपादक

प्रभात झा, सांसद

कार्यकारी संपादक

डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक

संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य

सत्यपाल

कला संपादक

धर्मेन्द्र कौशल

विकास सैनी

सदस्यता शुल्क

वार्षिक : 100/-

त्रि वार्षिक : 250/-

संपर्क

InL;rk : +91(11) 23005798

Qksu (dk-) : +91(11) 23381428

QDl : +91(11) 23387887

पता : डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

ई-मेल

kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी-36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली-55 से मुद्रित करा के, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक - प्रभात झा

विषय-सूची

आवरण कथा : महंगाई, भ्रष्टाचार व एफडीआई

यूपीए की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ भाजपा का देशव्यापी प्रदर्शन...... 7

गुजरात विधानसभा चुनाव 2012

गुजरात चुनावों में भारी विजय की ओर बढ़ती हुई भाजपा........................ 13

वैचारिकी

जीवन का ध्येय

-दीनदयाल उपाध्याय.. 16

लेख

सरदार पटेल की विलक्षण उपलब्धि

-लालकृष्ण आडवाणी.. 20

बिना पतवार की नाव है यूपीए सरकार

- डॉ. मुरली मनोहर जोशी.. 23

श्रद्धांजलि

बाल ठाकरे... 15

मुख पृष्ठ : *खुदरा व्यापार में एफडीआई के विरोध में दिल्ली प्रदेश भाजपा द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी, भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह, दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता श्री विजय कुमार मल्होत्रा एवं दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री विजेन्दर गुप्ता।*

ऐतिहासिक चित्र

रैली का नेतृत्व करते तत्कालीन जनसंघ नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी

नकल से सफलता नहीं

महापुरुषों का जीवन पढ़कर उनके गुण अपने जीवन में उतारना तो ठीक है, पर यदि उनके रंग-रूप की नकल करने का प्रयास किया, तो प्राय: हँसी ही बनती है।

एक बार किसी कार्यकर्ता ने शिवाजी के विश्वस्त साथी तानाजी मालसुरे की जीवनी पढ़ी। वह उससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने विचार किया जिस गाँव में मुझे नयी शाखा स्थापित करनी है, यदि वहाँ मैं तानाजी जैसे कपड़े पहनकर जाऊँ, तो लोग शीघ्र आकर्षित होंगे और मेरा कार्य सरल हो जाएगा। उसने वहाँ खबर भिजवा दी कि कल शाम को मैं तानाजी बनकर गाँव में आऊँगा। अगले दिन उसने किराये पर एक घोड़ा, सैनिक के कपड़े, पगड़ी, तलवार आदि ली और सजधज कर घोड़े पर बैठकर गाँव की ओर चल दिया। गाँव दूर था, अत: वहाँ पहुँचने में तीन-चार घंटे लग गये। गाँव में खबर थी ही, लोग चौपाल पर एकत्र थे। सबने ताली बजाकर उसका स्वागत किया। गाँव के मुखिया ने उनके गले में माला डालकर कहा - आइये महाराज उतरिये, मेरे घर चलिये। पर वह नकली 'तानाजी' घोड़े से उतरे कैसे ? उसे घोड़े पर बैठने का अभ्यास तो था नहीं। अत: चार घंटे की सवारी से उसकी टाँगे जाम हो गयीं। उन्होंने सीधी होने से मना कर दिया।

मुखिया जी समझ गये। उन्होंने कुछ लोगों की सहायता से उन्हें घोड़े से उतारा। वे जिस स्थिति में घोड़े पर बैठे थे, उसी स्थिति में उतर कर खड़े हो गये। चार कदम चलना भी उनके लिए संभव नहीं था। मुखिया जी ने कई दिन तक उनकी टाँगों की सिकाई और मालिश करवायी, तब वे सामान्य स्थिति में आये।

स्पष्ट है कि समाज के काम में महत्त्व मन की भावना का है, नकल का नहीं।

-'श्री गुरुजी बोधकथा' से साभार

इनका कहना है...

''आमिर अजमल कसाब को तो काफी देर बाद फांसी दी गई लेकिन सरकार अफजल गुरू को अभी तक क्यों बचाए हुए है। अफजल गुरू का अपराध कसाब से भी ज्यादा भयंकर और गम्भीर था लेकिन वोटों की लालची कांग्रेस सरकार ने अब तक उसे बचा रखा है।''

-नितिन गडकरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा

''सरकार संसद और कैग दोनों का अवमूल्यन कर रही है जो लोकतंत्र के लिए संकट है। इस सरकार के पास बहुमत तो है नहीं और बगैर जनादेश के वह किस प्रकार बैसाखियों पर खड़ी है, इसे सरकार इस सत्र के आइने में देख लेगी। कुल मिलाकर सरकार बिना पतवार की नाव की तरह समस्याओं के तूफान में दिशाहीन बनी हुई है।''

-डॉ. मुरली मनोहर जोशी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा

''आगामी चुनावों में भ्रष्टाचार, महंगाई, मुद्रास्फीति, खुदरा बाजार में मल्टी-ब्रांड एफडीआई, कृषि संकट, किसानों की पीड़ा और टूटे वायदे प्रमुख मुद्दे होंगे। और लोगों के सामने भाजपानीत एनडीए ही एकमात्र विकल्प रहेगा।''

-वेंकैया नायडू, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा

''देश के 65 फीसद किसानों के पास आय का अन्य कोई साधन नहीं है। वे मजबूरी में कृषि कार्य कर रहे हैं। देश का पेट भरने वाला किसान खुद बर्बादी की कगार पर खड़ा है। इसके पीछे कांग्रेस सरकार की किसान और गांव विरोधी नीतियां ही जिम्मेदार हैं।''

-राजनाथ सिंह, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा

व्यंग्य चित्र

सम्पादकीय

जनविरोधी निर्णय लेने के रोग से ग्रस्त है कांग्रेस

बहुब्राण्ड खुदरा व्यापार में एफडीआई पर पूरा देश आंदोलित है। जनता सड़कों पर उतर रही है। जगह-जगह इसका विरोध हो रहा है। देश के खुदरा व्यापारी से लेकर किसान तक कांग्रेस नीत संप्रग सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध मोर्चा खोल चुके हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों से लेकर सामाजिक संस्थाएं तक इस मुद्दे पर मुखर रूप से अपना विरोध जता चुकी हैं। यहां तक कि संप्रग में शामिल दल भी इस निर्णय का खुलकर विरोध कर चुके हैं। और तो और केरल के कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री श्री ऊमन चण्डी ने भी इस निर्णय के खिलाफ बयान दिया है। फिर भी यह विचित्र विडम्बना है कि कांग्रेस इस पर पुनर्विचार को तैयार नहीं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस को जनविरोधी निर्णय लेने का रोग लग चुका है, वह इस देश की जनहित को ही दांव पर लगा अपनी राजनीतिक गोटियां खेलना चाहती है।

आखिर कांग्रेस चाहती क्या है? वर्तमान प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जब राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष थे तब वे एफडीआई का कड़ा विरोध कर रहे थे। अब प्रधानमंत्री के रूप में वे इसके घोर समर्थक बन बैठे हैं। पिछली बार जब कांग्रेस ने दिसम्बर 2011 में इस निर्णय को लागू करना चाहा था तब भारी जनविरोध के कारण उसने इस निर्णय को रोक दिया था। साथ ही कांग्रेस नीत संप्रग सरकार ने संसद के दोनों सदनों में यह आश्वासन दिया था कि बिना पूरे देश को विश्वास में लिए वह इस निर्णय को लागू नहीं करेगी। बाद में सरकार ने इस निर्णय पर आम सहमति बनाने के लिए कोई पहल नहीं की। फिर एकाएक इस निर्णय को लागू करने का फैसला ले लिया गया और अब जब संसद का सत्र शुरु हो चुका है सर्वदलीय बैठकों और 'डिनर-डिप्लोमेसी' का खेल खेला जा रहा है। पहले तो निर्णय ले लिया गया और अब जब सड़क से लेकर संसद तक इसका भारी विरोध हो रहा है, तो आम सहमति बनाने का दिखावा किया जा रहा है। इससे पहले कभी कांग्रेस ने विपक्ष को विश्वास में लेने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। अब जबकि विरोध अपने घर में ही होने लगा तो विपक्ष की याद आ रही है। वह भी ऐसे मुद्दे पर जिसका विपक्ष कभी समर्थन नहीं कर सकती। इन सबके पीछे कांग्रेस की मंशा साफ नहीं। ना तो इसकी नीयत साफ है ना ही नीति।

खुदरा व्यापार भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत कड़ी है। करोड़ों लोगों का रोजगार इससे जुड़ा है। जब इंसान हर तरफ से थक-हार जाता है, जब और कहीं उसको रोजगार नहीं मिल पाता तब छोटी-मोटी पूंजी जुगाड़कर खुदरा व्यापार के सहारे अपना एवं अपने परिवार का पेट पालने की कोशिश करता है। इसके माध्यम से वह केवल अपना एवं अपने परिवार का पेट ही नहीं पालता, वह स्वावलंबी हो एक स्वतंत्र नागरिक की हैसियत से समाज में अपना स्थान बना जीवन यापन करता है। एफडीआई के सहारे इस देश में वाल मार्ट जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने व्यापारिक साम्राज्य का विस्तार करेंगी। करोड़ों लोग बेरोजगार कर दिए जायेंगे। इसके बदले कुछ हजार लोगों को इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों में नौकरियां मिल सकती हैं पर ना तो वे स्वतंत्र होंगे ना स्वावलंबी। वे एक नई व्यवस्था के दास होंगे और उनके हाथ इन कंपनियों के कायदे-कानूनों की जंजीरों से बांध दिये जायेंगे। छोटे-छोटे व्यापारियों को वालमार्ट जैसे बड़े पूंजी वाले कंपनियों के साथ दौड़ लगानी पड़ेगी। इनके धंधे चौपट हो जायेंगे और इनके परिवार सड़कों पर आने को विवश हो जायेंगे। एक और तर्क दिया जा रहा है कि किसानों को फायदा मिलेगा, बिचौलिए खत्म हो जाएंगे। यह

केवल एक झांसा है। जब व्यापार पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों की 'मोनोपॉली' होगी तब किसी को क्या फायदा होगा? किसानों को उनकी उपज मनमाने दामों पर बेचने को मजबूर किया जाएगा। विश्व में जिन देशों में ये बड़ी कंपनियां आईं वहां पर किसान से लेकर व्यापारी एवं उपभोक्ता तक कराह रहे हैं। बेरोजगारी की बड़ी भयानक समस्या खड़ी हो गई है। अमरीका तक इन कंपनियों के कारण बेरोजगारी के दंश झेल रहा है। यदि इन कंपनियों से फायदा हुआ होता तो अमरीका के राष्ट्रपति बराक ओबामा अपने देश के लोगों से छोटे दुकानदारों से सामान खरीदने की अपील नहीं कर रहे होते।

लगातार चुनावों में मिली हार ने कांग्रेस को 'आत्म मंथन' के स्थान पर 'आत्महत्या' करने की राह पर धकेल दिया है। 'आर्थिक सुधारों' के नाम पर इसने जनता पर गाज गिराने की ठान ली है। एक तरफ जहां भ्रष्टाचार के बड़े-बड़े खुलासे हो रहे हैं वहीं महंगाई अपने चरम पर है। डीजल-पेट्रोल के दाम बढ़ाने के साथ-साथ इसने कुकिंग गैस का दाम बढ़ा उसका कोटा तय कर कोढ़ में खाज का काम किया है। पहले से ही महंगाई ने जनता की कमर तोड़ रखी है अब उसका रोगजार भी छीना जाने वाला है। यह कैसा 'आर्थिक सुधार' है? इससे किसको लाभ मिलने वाला है? चंद 'आर्थिक सुधारों' के पक्षधरों की वाहवाही लूटने के लिए भारतीय अर्थ व्यवस्था से खेला जा रहा है। क्या यह कहना गलत होगा कि सरकार विदेशी ताकतों के आगे झुकने में तो हिचकिचा नहीं रही लेकिन देश की आवाज सुनना इसे गवारा नहीं।

इस देश की जनता सब देख व सुन रही है। उसने घोटालों की लम्बी फेहरिस्त देखी है। जनता बार-बार बढ़ते दामों का झंझावत पिछले आठ वर्षों से लगातार झेलती चली आ रही है। आर्थिक सुधार के दावों के बावजूद देश का विकास ठप्प है। प्रधानमंत्री 'मौन' हैं, संसद में मुंह पर ताला लगा दिया गया है, कांग्रेस जोड़-तोड़ के प्रपंच में लगी है। पर जनता हिसाब मांग रही है। जनता चुनावों में कांग्रेस को लगातार धूल चटा रही है पर कांग्रेस है कि कोई सबक ही नहीं सीखना चाहती। ऐसे में भाजपा जनता की आवाज बन रही है। सड़क से लेकर संसद तक भाजपा ने खुदरा व्यापार में एफडीआई का विरोध कर जनता के दर्द को आवाज दिया है। परन्तु संघर्ष अभी और तेज होना बाकी है। कांग्रेस जनता की आवाज को दबाने का कुचक्र रच रही है, ऐसे में सावधान रहना होगा। जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरते हुए देश को कांग्रेस के जनविरोधी नीतियों से मुक्ति दिलाना एक बड़ा दायित्व है जिसे भाजपा को तत्परता से निभाना पड़ेगा।■

अगरतला

मनमोहन सरकार आईसीयू में है : नितिन गडकरी

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने केंद्र की यूपीए सरकार पर हमला करते हुए कहा कि मनमोहन सरकार आईसीयू में है। यह सरकार कभी भी दम तोड़ सकती है। इसके साथ ही उन्होंने दावा करते हुए कहा कि अगले चुनाव में भाजपा की जीत होगी और केंद्र में हमारी सरकार बनेगी।

गत 22 नवम्बर को अगरतला में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री नितिन गडकरी ने कहा कि केंद्र की यूपीए सरकार अंतिम सांसें गिन रही है। इसके साथ ही केंद्र में भाजपा द्वारा सरकार बनाने का समय आ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपीए सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने में पूरी तरह से नाकाम रही है। गडकरी ने कहा कि भाजपा शासित राज्यों की स्थिति बिल्कुल अलग है। उन राज्यों में सरकारें पूरी तरह से सक्रिय हैं और हर तरह से कानून व्यवस्था का राज है।

श्री गडकरी ने कहा कि अब केंद्र में भाजपा के सरकार बनाने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि हम अच्छी सरकार देंगे और देश में सामाजिक सौहार्द कायम होगा। उन्होंने बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि बांग्लादेश से लगती सीमा को सील किया जाना चाहिए और अवैध घुसपैठ पर प्रभावी तरह से रोक लगनी चाहिए। श्री गडकरी ने माओवाद और आतंकवाद के प्रति लोगों को आगाह करते हुए कहा कि देश की सुरक्षा को इससे बहुत खतरा है। ■

यूपीए की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ भाजपा का देशव्यापी प्रदर्शन

कांग्रेस नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार के शासन में हुए महाघोटालों और बेलगाम महंगाई के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने संसद सत्र के एक दिन पहले 21 नवम्बर को सड़कों पर जबर्दस्त हल्ला बोला। भाजपा ने पूरे देश में महंगाई, भ्रष्टाचार, घोटालों एवं खुदरा बाजार में विदेशी निवेश के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, धरने, रैलियां, सभाएं एवं जनजागरण मार्च आयोजित किए।

दिल्ली सहित देश के विभिन्न भागों, की राजधानी एवं जिला केन्द्रों पर हुए विरोध प्रर्दशन, धरनों, सभाओं, मार्च, में पार्टी के प्रमुख केन्द्रीय एवं प्रान्तीय नेताओं ने भाग लिया। इससे पूर्व पार्टी ने तहसील एवं मण्डल स्तर तक मंहगाई, भ्रष्टाचार, एफ0डी0आई0 रिटेल को लेकर 20 अक्टूबर से प्रभावी जनजागरण एवं सम्पर्क अभियान चला रखा है, जिसके तहत अब तक देश भर के लगभग तीन हजार चार सौ अस्सी विधानसभा क्षेत्रों में 30 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं एवं आम लोगों से पार्टी कार्यकर्ताओं ने ''सम्पर्क-संवाद'' कार्यक्रम पूरा कर लिया गया है। विभिन्न राज्यों में नुक्कड़ नाटकों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भी पार्टी ने मंहगाई एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रभावी सम्पर्क-संवाद किए। भाजपा उपाध्यक्ष एवं केन्द्रीय चुनाव प्रबन्धन एवं कार्यक्रम अभियान के प्रभारी श्री मुख्तार अब्बास नकवी के अनुसार, 20 अक्टूबर से ''मंहगाई-भ्रष्टाचार'' के खिलाफ देश भर में चल रहे ''सम्पर्क-संवाद'' अभियान के तहत अब तक पार्टी कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश की 403 विधान सभा क्षेत्रों में मतदाताओं एवं लोगों से सम्पर्क किया, राजस्थान की 200 विधानसभाओं में, मध्यप्रदेश की 230 विधानसभा में, छत्तीसगढ़ की 90 विधान सभा क्षेत्रों में, कर्नाटक की 224 विधानसभा, महाराष्ट्र की 288 विधानसभा, उत्तराखण्ड की 70 विधानसभा, पश्चिम बंगाल की 294 में 142 विधान सभा, झारखण्ड की 81 विधानसभा, हरियाणा की 90 विधानसभा, दिल्ली की 70 विधानसभा, आन्ध्र प्रदेश की 294 में 222 विधान सभा, बिहार की 243 विधान सभा जम्मू-कश्मीर की 87 में 31 विधान सभा क्षेत्रों में, केरल के 140 में 82 विधान सभा, असम की 126 में 92 विधान सभा, पंजाब की 117 में 91 विधान सभा, गुजरात की 182 विधान सभा, उडीसा के 147 में 112 विधान सभा, अरुणाचल के 60 में 40 विधान सभा, त्रिपुरा में 60 में 32 विधान सभा, पुद्दुचेरी की 30 विधानसभा में 25 विधान सभा क्षेत्रों, तमिलनाडु के 234 में 168 विधासभा, गोवा के 40 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा ने सफलता पूर्ण ''सम्पर्क-संवाद'' कार्यक्रम पूरा कर लिया है। इसी प्रकार अन्य राज्यों में भी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा जनजागरण एवं ''सम्पर्क-संवाद'' कार्यक्रम चलाए गये हैं। इस जनजागरण एवं ''सम्पर्क-संवाद,, कार्यक्रम में पार्टी करोड़ों मतदाताओं और लोगों तक अपना संदेश देने में सफल रही है।

हम यहां 21 नवम्बर को यूपीए की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ भाजपा द्वारा आयोजित देशव्यापी प्रदर्शन के संक्षिप्त समाचार प्रस्तुत कर रहे हैं :

दिल्ली

भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेसनीत यूपीए सरकार के विरोध में संसद मार्ग पर प्रदर्शन किया और जंतर मंतर से प्रधानमंत्री निवास की ओर कूच करते समय गिरफ्तारी दी। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री मुख्तार अब्बास नकवी, दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा, राष्ट्रीय महामंत्री श्री विजय गोयल, राष्ट्रीय मंत्री सुश्री आरती मेहरा, आदि नेतागण शामिल थे।

प्रधानमंत्री निवास की ओर मार्च करने से पहले जंतर मंतर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए श्री नितिन गडकरी ने कांग्रेस सरकार से सवाल किया कि आमिर अजमल कसाब को तो काफी देर बाद फांसी दी गई लेकिन सरकार अफजल गुरू को अभी तक क्यों बचाए हुए है। अफजल गुरू का अपराध कसाब से भी ज्यादा भयंकर और गम्भीर था लेकिन वोटों की लालची कांग्रेस सरकार ने अब तक उसे बचा रखा है। उन्होंने भ्रष्टाचार, घोटालों, महंगाई, एफडीआई आदि पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि जो

भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, वही भारत आज विदेशों के आगे कटोरा लेकर क्यों खड़ा है? कांग्रेस सरकार विदेशी निवेश के पीछे इतनी दीवानी क्यों है? क्या भारत के व्यापारी और उद्यमी देश को आगे ले जाने में समर्थ नहीं हैं? देश की जनता इसका जवाब चाहती है।

श्री राजनाथ सिंह ने विस्तार से देश की बदहाली पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि आज भी देश के किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। सरकार किसानों को उनकी उपज की लागत भी नहीं दे रही है। देश के 65 फीसद किसानों के

पास आय का अन्य कोई साधन नहीं है। वे मजबूरी में कृषि कार्य कर रहे हैं। देश का पेट भरने वाला किसान खुद बर्बादी की कगार पर खड़ा है। इसके पीछे कांग्रेस सरकार की किसान और गांव विरोधी नीतियां ही जिम्मेदार हैं। गांव का कोई भी युवक शहर मजबूरी में आता है क्योंकि उसे अपने गांव में रोटी नसीब नहीं है।

सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि केंद्र और दिल्ली की कांग्रेस सरकारों ने अपनी लूटखोर और जनविरोधी नीतियों के कारण आम जनता का जीना मुश्किल कर दिया है। अब तो कांग्रेस सरकार लोगों को पेट भर भोजन भी करने देना नहीं चाहतीं, इसीलिए रसोई गैस सिलेंडरों पर कोटा तय कर दिया गया है। दिल्ली के 4 लाख गरीबों को इस सरकार ने मिट्टी का तेल देना बंद कर दिया है। इन परिवारों की इतनी हैसियत नहीं है कि वे कालाबाजार से 1400 रुपए का रसोई गैस सिलेंडर खरीदकर अपना और अपने परिवार का पेट पालन करें। लोगों के जले पर नमक छिड़कने के लिए सरकार ने दिल्ली सांख्यिकी पुस्तिका जारी की है, जिसके अनेक आंकड़े भ्रामक और लोगों को गुमराह करने वाले हैं। लगता है आंकड़ों के मायाजाल में शीला सरकार अपनी नाकामियों को छिपाना चाहती है। दिल्ली की बदहाल शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, पर्यावरण व्यवस्था लोगों से छिपी नहीं है। यहां महंगाई हर रोज बढ़ रही है। सरकार की नीतियां जनता की जेब खाली करने वाली हैं। यह सरकार दिल्ली में सर्किल रेट बढ़ाने जा रही है, जिससे लोगों के मकान का सपना अधूरा रह जाएगा। दिल्लीवासियों ने कांग्रेस सरकार को अब और बर्दाश्त न करने की कसम खा ली है। इसका परिणाम आने वाले चुनावों में देखने को मिलेगा।

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि एफडीआई आने से देश का उद्योग-व्यापार चौपट हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने बगैर सोचे समझे एफडीआई लाने का जनविरोधी निर्णय किया है। उसे यह नहीं मालूम कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था यहां के वाणिज्य और व्यापार पर ही निर्भर है। इसमें विदेशी निवेश आने से लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार होंगे और दिल्ली का 100 साल पुराना व्यापारिक चरित्र चौपट हो जाएगा। मुख्यमंत्री जानती हैं कि दिल्ली में खेती न के बराबर है फिर भी वे विदेशी निवेश का रेड कारपेट स्वागत कर रही हैं। उन्हें दिल्ली की अर्थव्यवस्था की समझ ही नहीं है। प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा ने केन्द्र और दिल्ली सरकार की जनविरोधी नीतियों, भ्रष्टाचारों, घोटालों की विस्तार से चर्चा की और कहा कि यह सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों को तिलांजलि दे चुकी है। राष्ट्रीय महामंत्री विजय गोयल ने कहा कि जब तक मनमोहन और शीला सरकार को अपदस्त नहीं किया जाता है देश और दिल्ली की जनता चैन की सांस नहीं ले पाएगा। सभा को राष्ट्रीय मंत्री आरती मेहरा, वाणी त्रिपाठी, डॉ. हर्षवर्धन सहित अनेक नेताओं ने संबोधित किया। धरने में प्रो. जगदीश मुखी, रमेश बिधूड़ी, प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, पवन शर्मा, विशाखा सैलानी, विजय जौली सहित अनेक विधायकों, पार्षदों व पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया।

मध्य प्रदेश

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री थावरचंद गेहलोत ने कहा कि कांग्रेस गठबंधन की यूपीए सरकार की गलत नीतियों के कारण आज देश के कोने-कोने में बेईमानी और भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है। विदेशी दबाव में योजनाबद्ध तरीके से खुदरा बाजार में 100 फिसदी विदेशी निवेश लाकर देश की आर्थिक और सार्वभौमिक एकता और अखण्डता को खतरा पहुंचाने का कार्य कांग्रेस की सरकार कर रही है। भाजपा 51 फिसदी से अधिक विदेशी निवेश का सड़क से

लेकर संसद तक जनता को साथ लेकर विरोध करती रहेगी।

श्री गेहलोत ने यह बात उज्जैन नगर एवं ग्रामीण जिला भाजपा द्वारा टॉवर चौक पर आयोजित हल्ला बोल धरना प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए कहीं। उन्होंने कहा कि योजनाबद्ध तरीके से विदेशियों के दबाव में लाये जा रहे एफडीआई के कारण देश के राजनीतिक परिदृश्य पर भी प्रभाव पड़ेगा। आम जनता

का देश के घोटालों और भष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए एफडीआई की वकालत की जा रही है। उन्होंने कहा कि खुदरा बाजार में 74 से 100 फिसदी विदेशी निवेश से देश की अर्थव्यवस्था तो चौपट होगी ही साथ ही लाखों करोड़ों लोगों के समक्ष रोजगार की समस्या भी खड़ी हो जायेगी।

कांग्रेस की नीति और नियत ठीक नहीं होने के कारण देश में महंगाई और भ्रष्टाचार का बोल-बाला है। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि समूचा विश्व जब आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है तो चीन में विकास की दर कैसे बढ़ रही है? महंगाई की दर वहां 3 प्रतिशत के आसपास है, जबकि भारत में विकास की दर 5 फिसदी से उपर नहीं पहुच पा रही है। महंगाई की दर 14 से 18 प्रतिशत तक हो गई है। दुनिया में सर्वाधिक महंगाई भारत में है यह सब कांग्रेस की गलत नीतियों का खामियाजा है।

श्री गेहलोत ने अटल जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की सराहना करते हुए कहा कि अटल जी की सरकार में बुनियादी वस्तुएं सहज उपलब्ध थी। विकास की दर 10.2 फिसदी तक पहुंच गई थी और महंगाई पूरी तरह नियंत्रण में थी। उन्होंने कहा कि केन्द्र की कांग्रेस सरकार आम जन से सरोकर रखने वाले सभी प्रजातांत्रिक आंदोलनों के प्रति गंभीर नहीं है। आंदोलन को पूर्व केन्द्रीय मंत्री डॉ.सत्यनारायण जटिया, नगर जिला अध्यक्ष श्री अनिल जैन कालुहेड़ा, ग्रामीण जिला अध्यक्ष डॉ.तेजबहादुरसिंह चौहान, प्रदेश सह प्रवक्ता श्री रूप पमनानी, महापौर श्री रामेश्वर अखण्ड समेत अनेक वरिष्ठ नेताओं ने भी संबोधित किया।

छतीसगढ़

महंगाई, भ्रष्टाचार और एफडीआई के विरोध में भाजपा ने प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में धरना-प्रदर्शन किया। इसके लिए सांसदों से लेकर पार्टी पदाधिकारियों तक ने जिलों की कमान संभाली। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने केन्द्र सरकार पर जमकर प्रहार किया। रायपुर में पार्टी के प्रदेश प्रभारी व राष्ट्रीय महामंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने प्रदर्शन की अगुवाई की। श्री नड्डा ने कहा कि महंगाई और भ्रष्टाचार के लिए केन्द्र सरकार जिम्मेदार है। एफडीआई का हर स्तर पर विरोध होगा। इसे देश में आने नहीं दिया जाएगा।

पश्चिम बंगाल

भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमती निर्मला सीतारमन ने केंद्र की यूपीए सरकार पर राजनीतिक दलों के साथ घमंडपूर्ण तरीके से आचरण करने का आरोप लगाया और कहा कि वह अब सीधे तौर पर जनता को उपेक्षित करने लगी है। कोलकाता स्थित प्रेसक्लब में 21 नवम्बर को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारों और घोटालों के आरोपों से घिरी केंद्र की कांग्रेस सरकार कह रही है कि उसे किसी की परवाह नहीं, यानि आम जनता की भी वह परवाह करने की जरूरत नहीं समझती। श्रीमती सीतारमन ने तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी की तर्ज पर ही केंद्र की मौजूदा सरकार को अल्पमत वाली सरकार करार दिया और कहा कि उसे अब सत्ता में बने रहने का अधिकार गंवा दिया है। मुंबई आतंकी हमले के दोषी अजमल कसाब को फांसी दिए जाने को बहरहाल उन्होंने केंद्र का एक सराहनीय कदम बताया और कहा कि यह देर से लिया गया सही निर्णय है। संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष राहुल सिन्हा ने संसद हमले के दोषी अफजल गुरू की फांसी की मांग उठाई। उन्होंने पूछा कि अफजल को सजा देने में केंद्र सरकार क्यों हिचकिचा रही है।

हरियाणा

भाजपा के राष्ट्रीय सचिव श्री मुरलीधर राव ने कहा कि केंद्र की यूपीए सरकार ने खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश की मंजूरी देकर वालमार्ट जैसी कंपनियों को आमंत्रित करके ईस्ट इंडिया कंपनी के नए अवतार को जन्म दिया है। लेकिन,

भाजपा एफडीआई मंजूरी को रद्द करवाकर ही दम लेगी। वे एफडीआइ के विरोध में एनडीए द्वारा घोषित राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन के तहत सोनीपत स्थित उपायुक्त कार्यालय के बाहर भाजपा-हजकां की ओर से आयोजित धरने को संबोधित कर रहे थे।

भाजपा नेता ने कहा कि एक समय देश को आजाद करवाने के लिए कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था और आज कांग्रेस रामलीला मैदान में रैली करके अंग्रेजों वापस आओ का नारा दे रही है। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के घोटाले पूरे विश्व में देश की बदनामी का कारण बन गए हैं। इसलिए भाजपा देश की बदनामी से परेशान होकर सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गई है। कांग्रेस की प्रदेश सरकार पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार जमीन घोटालों का पर्याय बन गई है। उन्होंने घोषणा की कि भाजपा-हजकां का गठबंधन मजबूत है। उन्होंने कहा कि काग्रेस की सरकार हटेगी तो देश में कांग्रेस का जड़ मूल से नाश हो जाएगा। धरने को विधायक कविता जैन, पूर्व सांसद किशन सांगवान, पूर्व विधायक देवीदास, प्रदेश मीडिया प्रभारी राजीव जैन, प्रदेश सचिव ललित बत्रा, आजाद नेहरा, मनोज जैन, हजकां जिलाध्यक्ष धर्मबीर खत्री, प्रभारी रणजीत कौशिक, एडवोकेट दिनेश अत्री आदि ने भी संबोधित किया।

भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि भाजपा देश में एफडीआई को लागू नहीं होने देंगी क्योंकि एफडीआई के लागू होने से जहां किसान तो बर्बाद होगा ही वहीं आम व्यापारी इससे प्रभावित होगा। श्री गुर्जर फरीदाबाद स्थित हार्डवेयर चौक पर जिला भाजपा द्वारा एफडीआई के विरोध में कांग्रेस सरकार का पुतला फूंकने के उपरांत उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर श्री गुर्जर ने कहा कि इस सरकार का केवल यही काम है कि वह अपने लाभ के लिए देश के ऊपर कुछ भी थोप दे। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने इस सरकार की कारगुजारियों का सदैव विरोध किया है और करती भी रहेगी। उन्होंने कहा कि एफडीआई से जहां देश के अन्य व्यापार पर पूरा असर होगा वहीं देश पूरी तरह से विदेशी हाथों में चला जायेगा जिसे हम सहन नहीं करेंगे। श्री गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस सरकार एक बार फिर हमारे देश को विदेशियों के हाथों गुलाम बनाना चाह रही है। उन्होंने कहा कि विदेशों से सम्पर्क बढ़ाकर यह देश को गिरवी रखने का मन बना चुकी है परंतु भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं होने देगी क्योंकि अब भाजपा के साथ जनता है। जनता आज समझ चुकी है कि कांग्रेस ने केवल उनसे वोट हासिल करके सत्ता पर काबिज होने तक ही उनका ध्यान रखा परंतु सत्ता हथियाने के पश्चात आज जनता को रोने के लिए छोड़ दिया है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष अजय गौड़ ने कहा कि कांग्रेस ने सदैव जनता को महंगाई, बेरोजगारी, भूख का तोहफा दिया है। आज गरीब, असहाय एवं मजदूर वर्ग का इंसान पूरी तरह से समाप्ति के कगार पर है।

इस मौके पर समस्त भाजपा पदाधिकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष चौ. कृष्णपाल के नेतृत्व में पैदल मार्च भी निकाला एवं जनता से आह्वान किया कि आगामी चुनावों में कांग्रेस को जड़ से उखाड़ दिया जाये।

उत्तर प्रदेश

देश में बढ़ती मंहगाई व कांग्रेस नीति यूपीए सरकार के घोटालों के खिलाफ देश व्यापी अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में जबरदस्त धरना-प्रदर्शन और ज्ञापन देने का कार्य किया। प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने बताया कि राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय महामंत्री अनंत कुमार, प्रदेश अध्यक्ष डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेई, सांसद लाल जी टण्डन ने धरने का नेतृत्व किया, जबकि गाजियाबाद में राष्ट्रीय महामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने नेतृत्व किया।

पार्टी प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने धरना प्रदर्शन की जानकारी देते हुए कहा कि वर्तमान यूपीए सरकार से समाज का हर वर्ग दुखी है। उन्होंने कहा यूपीए सरकार ने वादा किया था कि सत्ता में आने पर 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। जबकि ठीक इसके विपरीत यूपीए सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों के दाम 24 बार बढ़ाये तथा उर्वकों की 12 बार कीमतें बढ़ाई। काले धन की वापसी का वादा किया गया किन्तु इसके विपरीत 700 नामों की सूची आने के बाद भी उसका खुलासा नहीं हो रहा। कांग्रेस की नीति रही है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना और ईमानदार को सताना। यूपीए सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार व घोटालों ने रिकार्ड बनाया है। आम आदमी परेशान है सरकार पर सवालिया निशान लगा रहे है। श्री पाठक ने सपा- बसपा से एफ.डी.आई. पर अपने दोहरे चरित्र से बाज आने को कहा। उन्होंने कहा सपा-बसपा एफ.डी.आई. के विरोध की तो बात करती है लेकिन जब सदन में यूपीए सरकार को गिराने की बात आती है तो ये दोनों दल यूपीए सरकार के साथ खड़े हो जाते है।

उन्होंने बताया लखनऊ में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेई, अनंत कुमार, लालजी टण्डन ने अगुवाई कि वही सहारनपुर में वीरेन्द्र सिंह सिरोही, गोरखपुर में योगी अदित्यनाथ, लखीमपुर में सुरेश खन्ना, अजय मिश्रा टेनी, संतकबीर नगर में विनोद पाण्डेय, सिद्धार्थनगर में नरेन्द्र सिंह,

रामपुर में डा0 नैपाल सिंह, हाथरस में रामनरेश अग्निहोत्री, अलीगढ़ में केदार सिंह, बदायूँ व शाहजहांपुर में धर्मपाल सिंह, मैनपुरी में मदन चौहान, कासगंज में रघुराज सिंह, एटा में पंकज गुप्ता, बरेली में अरूण कुमार, उन्नाव में हृदयनारायण दीक्षित, बनारस में सिद्धार्थनाथ सिंह, इलाहाबाद में डा0 रमापतिराम त्रिपाठी, मुरादाबाद में लज्जारानी गर्ग, बहराइच में गोपाल टण्डन, सीतापुर में संतोष सिंह, सुभाष त्रिपाठी, अम्बेडकरनगर में परशुराम कुशवाहा, रायबरेली में श्रीमती पूर्णिमा वर्मा, गोण्डा में दिवाकर सेठ, बाराबंकी में शरद अवस्थी, बलरामपुर में जमुना प्रसाद चतुर्वेदी, शैलेन्द्र सिंह शैलू, श्रावस्ती में शेष नारायण मिश्रा, बागपत में राजेन्द्र कुमार, बिजनौर में अशोक कटारिया, शामली में नीरज शर्मा, मुजफरनगर में आश्विनी त्यागी, बुलन्दशहर में नवाब सिंह नागर, अमरोहा में श्रीमती कमलेश सैनी, हापुड़ में अमित अग्रवाल, संभल में सूर्यप्रकाश पाल, कुशीनगर में डा0 समीर सिंह, देवरिया में उपेन्द्र शुक्ला, बस्ती में अष्टभुजा प्रसाद, मऊ में राम चौहान, बलिया में विनोद राय, गाजीपुर मनोज सिंह, प्रभुनाथ चौहान, चन्दौली में गोविन्द नारायण शुक्ल, जौनपुर में विभूतिनारायण सिंह, सुल्तानपुर में श्रीमती सुमन सिंह, छत्रपति शाहूजी महाराजनगर में डा0 एम.पी. सिंह, संत रविदास नगर में डा0 राकेश त्रिवेदी, मिरजापुर में लक्ष्मण आचार्य, सोनभद्र में जयप्रकाश चतुर्वेदी, प्रतापगढ़ में सरदार सिंह,फतेहपुर में सतीश महाना व राधेश्याम गुप्ता ने धरना प्रदर्शन का नेतृत्व किया।

उत्तराखण्ड

देहरादून स्थित पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क में भारतीय जनता पार्टी ने केन्द्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के विरोध में धरना दिया। देहरादून में धरने-प्रदर्शन का नेतृत्व भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कलराज मिश्र के हाथों में था।

भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कलराज मिश्र ने धरने को सम्बोधित करते हुए कहा कि यूपीए सरकार ने पूरे देश में जो घोटाले किये हैं तथा एफडीआई के माध्यम से विदेशी कंपनियों को देश में लाया जा रहा है और यह कांग्रेस का राष्ट्रविरोधी कदम है। प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह चुफाल ने हल्द्वानी में भाजपा के प्रदर्शन की कमान संभाली है। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों का कारण आज बढ़ती मंहगाई से आम आदमी परेशान है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने कसाब को फांसी दे दी है, लेकिन एक आतंकवादी को केन्द्र सरकार ने चार वर्षो तक सुरक्षित रखा और उसकी सुरक्षा व्यवस्था पर इतना धन व्यय किया गया, यह काम पहले ही कर दिया जाना चाहिए था। यदि उसे पहले ही फांसी दे दी जाती तो इतना धन बर्बाद नहीं होता।

पंजाब

अमृतसर में जिला भाजपा इकाई द्वारा एफडीआई के विरोध में रैली आयोजित की गई। इस रैली में वरिष्ठ भाजपा नेता व गुजरात प्रदेश भाजपा प्रभारी श्री बलबीर पुंज एवं श्री नवजोत सिंह सिद्धू शरीर पर बेड़ियां व जंजीरें डालकर आए हुए थे। इस अवसर पर श्री बलबीर पुंज ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि एफडीआई के मुद्दे पर संसद में सरकार को घेरा जाएगा। श्री सिद्धू ने कहा कि रिटेल में विदेशी निवेश व्यापारियों को 'सेल्समैन' बना देगी। रोजगार के साधन कमजोर हो जाएंगे। बड़ी कंपनियां चीन का बना हुआ माल बेचेंगी। जिससे भारतीय बाजार कमजोर होगा। करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। रिटेल का व्यापार कुछ अमीर घरानों को सौंपने की केंद्र सरकार तैयारी कर रही है। छोटा व्यापारी भारतीय जनता पार्टी के दिल की धड़कन है। उनके हितों की रक्षा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मंत्री श्री अनिल जोशी ने कहा है कि रिटेल में एफडीआई के मुद्दे पर सरकार

कटघरे में खड़ी है। सरकार एफडीआई के मामले पर कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों व बड़े औद्योगिक घरानों को लाभ पहुंचाना चाहती है। इस अवसर पर मेयर बख्शी राम अरोड़ा, पूर्व मेयर श्वेत मलिक, प्रभजीत रटौल सहित अनेक वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। रिटेल में एफडीआई के विरोध में पूर्व मंत्री श्रीमती लक्ष्मीकांता चावला कार्यकर्ताओं के साथ भंडारी पुल पर पहुंची। जहां कार्यकर्ताओं ने एफडीआई के विरोध में केंद्र

सरकार को जमकर कोसा। इस अवसर पर भाजपा के जिला उप प्रधान डा. राकेश शर्मा, राजेश पाठक, देव कुमार आदि उपस्थित थे।

झारखंड

महंगाई, भ्रष्टाचार और खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के विरोध में भारतीय जनता पार्टी कार्यकत्ताओं ने रांची स्थित राजभवन के समक्ष हल्ला-बोल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत रांची महानगर के हजारों कार्यकर्ताओं ने राजभवन के निकट एकदिवसीय धरना दिया। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिनेशानन्द गोस्वामी ने कहा कि रिटेल में एफडीआई को अनुमति देकर कांग्रेस 25 करोड़ लोगों की जीविका छिनना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विदेशी ताकतों के एजेंट के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पहचान महंगाई बढ़ाने वाली पार्टी और भ्रष्टाचार में लिप्त रहकर जनता की गाढ़ी कमाई के अरबों रुपये लूटने वाले के रूप में हो गयी है। उन्होंने कहा कि खुदरा क्षेत्र में एफडीआई को मंजूरी देकर पांच करोड़ लोगों को सीधे तौर पर बेरोजगार बनाने तथा 25 करोड़ लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचाने का काम करने जा रहा है। आज डीजल, कीटनाशक दवा, बीज एवं रासायनिक खाद में अप्रत्याशित मूल्य वृध्दि कर देश के किसानों के उत्पाद का लागत मूल्य बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि जिस बिचौलियों को हटाने की बात कांग्रेस कर रही है, अब कांग्रेस खुद एक बड़ा बिचौलिये बन कर विदेशी कंपनी से इस एवज में लगातार कमाएंगी। प्रदेश महामंत्री अनंत ओझा ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए-2 में जितना जनविरोधी निर्णय लिया गया है, उससे इस देश की आर्थिक सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा एवं गरीब एवं मध्यम वर्गीय जनता को आर्थिक सुरक्षा विशेष रूप से खतरे में पड़ने जा रही है। भाजपा कांग्रेस के इस मंसूबे को कभी सफल नहीं होने देगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए रांची महानगर अध्यक्ष सत्यनारायण सिंह ने कहा कि आज गांधी परिवार का एक सदस्य रॉबर्ट बडेरा पर जब कराड़ों रुपये का भ्रष्टाचार का आरोप लगा, तो कांग्रेसी इसे ढकने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विदेशी ताकतों की एक एजेन्ट के रूप में काम कर रही है। कांग्रेस का काम है महंगाई बढ़ाना और भ्रष्टाचार करना। उसे आम जनता की परेशानियों से कोई मतलब नहीं है। श्री सिंह ने कहा कि कांग्रेस एफडीआई को मंजूरी देकर करोड़ो लोगों को बेरोजगार करने का काम करने जा रही है। कार्यक्रम का संचालन मनोज मिश्रा और धन्यवाद ज्ञापन ग्रामीण जिलाध्यक्ष मनोज वाजपेयी ने किया।

राजस्थान

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती किरण माहेश्वरी ने कहा है कि भ्रष्टाचार महंगाई बढ़ती बेकारी और खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश पर कांग्रेस सरकार कुंभकर्णी नींद में सो रही है। श्रीमती माहेश्वरी ने राजसमंद जिले के भीम कस्बे में पार्टी द्वारा आयोजित हल्ला बोल रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आम जनता को हो रही भीषण कठिनाईयों पर सरकार में किंचित भी संवेदना नहीं है। इसीलिए आज सारे देश में गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए भाजपा ने हल्ला बोला है। श्रीमती माहेश्वरी ने कहा कि किसान मजदूर कर्मचारी और छोटाव्यापारी सभी महंगाई से त्रस्त है। कांग्रेस के नेता जनता की वेदना की निर्लज्जता से हंसी उडा रहे है। कांगेस भ्रष्टाचार के नित नए कीर्तिमान बना रही है। आकाश जमीन पाताल कोई भी कांग्रेस के भ्रष्टाचार से बचा नहीं है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की पोल खोलने

वालों को अपमानित करने का प्रयास कर रही है। श्रीमती माहेश्वरी ने इस बात पर भी रोष व्यक्त किया कि सरकार ने लोकसभा में खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश के पूर्व आम सहमति बनाने का दिया हुआ वचन भंग कर दिया। मुंबई हमले के दोषी आमिर अजमल कसाब को कल फांसी पर लटकाये जाने के संबंध में उन्होंने कहा कि कसाब को मृत्यु दण्ड देने में काफी विलम्ब किया गया। संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरू के बारे में चुप्पी क्यों है? ■

गुजरात चुनावों में भारी विजय की ओर बढ़ती हुई भाजपा

हमारे संवाददाता द्वारा

गुजरात विधानसभा चुनावों की प्रक्रिया की शुरूआत होते ही, अधिकांश चुनाव-उद्घोषकों ने भविष्यवाणी की है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पहले से भी अधिक सीटें जीतकर फिर से सत्ता में आने की तैयारी में है। गुजरात में चुनाव का काम चुनाव तारीखों की औपचारिक घोषणा से शुरू हो गया जिसके अन्तर्गत मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री वी.एस. सम्पत ने कार्यक्रम की तारीखें 3 अक्तूबर 2012 को की थी। गुजरात में चुनावों की घोषणा के अनुसार इसे दो चरणों में कराया जाएगा। प्रथम चरण का चुनाव 13 दिसम्बर 2012 और दूसरे चरण का चुनाव 17 दिसम्बर 2012 को कराया जाएगा। मतगणना 20 दिसम्बर 2012 को होगी। गुजरात में 182 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र हैं जिसमें से 13 सीटें अनुसूचित जाति और 26 सीटें अनु. जनजाति प्रत्याशियों के लिए आरक्षित हैं। भाजपा 1995 से राज्य में बहुमत में है और 2012 चुनावों के बाद विधानसभा में उसका नियंत्रण बने रहने की संभावना बताई गई है।

गुजरात विधानसभा चुनाव 2012 कार्यक्रम

गुजरात चुनाव चरण-I कार्यक्रमः

प्रथम चरण के लिए चुनाव अधिसूचना	:	17 नवम्बर 2012
'' नामांकन करने की तारीख	:	24 नवम्बर 2012
'' आवेदन पत्रों की जांच	:	26 नवम्बर 2012
'' नाम वापसी की तारीख	:	28 नवम्बर 2012
'' चुनाव की तारीख	:	13 दिसम्बर 2012

गुजरात चुनाव चरण-II कार्यक्रम

द्वितीय चरण के लिए चुनाव अधिसूचना	:	23 नवम्बर 2012
'' नामांकन करने की तारीख	:	30 नवम्बर 2012
'' आवेदन पत्रों की जांच	:	01 दिसम्बर 2012
'' नाम वापसी की तारीख	:	03 दिसम्बर 2012
'' चुनाव की तारीख	:	17 दिसम्बर 2012

गुजरात चुनाव 2012 के परिणाम (सभी चरणों के लिए) 20 दिसम्बर 2012

एक रिपोर्ट के अनुसार गुजरात राज्य में नए मतदाताओं की संख्या में 12,77,662 की बढ़ोतरी हुई है। अब गुजरात में कुल मतदाताओं की संख्या 3,78,15,306 है। 2012 में गुजरात की जनसंख्या 6.15 करोड़ तक पहुंच गई है। इस प्रकार यहां 61.45 प्रतिशत मतदाता है। गुजरात के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुश्री अनीता करवाल ने इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए कहा कि गुजरात में 3.78 करोड़ मतदाता है जिनमें से 18 से कम आयु के लोगों का प्रतिशत 38.55 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि इन मतदाताओं ने जहां 12,77,662 की बढ़ोतरी हुई है तो वहीं 3,75,926 मतदाताओं के नाम कटे हैं।

इस प्रकार कुल मतदाताओं की संख्या में 9,01,736 की वृद्धि हुई, जो कुल मतदाताओं का 2.41 प्रतिशत है। करवाल ने आगे कहा कि गुजरात में चुनाव बूथों की संख्या 44,496 होगी जिसमें से 30,125 बूथ गांवों में होंगे तथा 14,371 बूथ शहरी क्षेत्रों में होंगे। यह सभी चुनाव केन्द्र 27,049 स्थानों पर स्थित हैं जिनमें 21,662 गांवों में है और 5,378 शहरों में। चुनाव आयोग ने 40 स्थानों पर विशेष व्यवस्था की है जहां 100 मतदाताओं से कम मतदाता होंगे। इसी प्रकार 235 ऐसे चुनाव केन्द्र ऐसे क्षेत्रों में होंगे जहां 200 से कम मतदाता होंगे और 814 ऐसे चुनाव केन्द्र होंगे जहां 300 से कम मतदाताओं को अपना वोट डालना होता है।

कांग्रेस जो 1990 से एक भी विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाई है, अब बुरी तरह से हताश और निराश है। भाजपा ने 1990 में विधानसभा चुनावों में 67 सीटों पर विजय प्राप्त की थी, उसमें 1995 में अपने बल पर विधानसभा चुनावों 121 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। तब से भाजपा को फिर से पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ी और भाजपा लोगों का गहन समर्थन प्राप्त कर बार-बार सत्ता में लौट कर आई। 1998 में हुए चुनावों में भाजपा ने 117 सीटे जीतीं

और 2002 में उसकी सीटों की संख्या बढ़कर 127 हो गई। 2007 में हुए चुनावों में भाजपा ने 117 सीटें जीतीं तो कांग्रेस केवल 59 सीटें ही जीत पाई। इस चुनाव में भाजपा के पक्ष में 49.12 प्रतिशत मत प्राप्त हुए तो कांग्रेस का समर्थन 38 प्रतिशत वोटों तक ही रह गया सीएनएन-आईबीएन की ओर से सेंटर फार दि स्टडी ऑफ डेवेलपिंग सोसाइटीज (सीएसडीएस) कराए गए एक चुनाव-पूर्व सर्वेक्षण के अनुसार भाजपा फिर से कांग्रेस को रौंद कर फिर से भारी बहुमत प्राप्त कर सत्ता में लौटेगी। इस सर्वेक्षण में गुजरात के 3658 मतदाताओं से बातचीत की और देखा गया कि लगभग 50 प्रतिशत मतदाता भाजपा के पक्ष में थे जबकि कांग्रेस मात्र 36 प्रतिशत पाकर बहुत पीछे रह गई।

श्री नरेन्द्र भाई मोदी के पक्ष में जबर्दस्त सरकार-समर्थक (सरकार-विरोधी नहीं) भावनाओं जो पांच वर्ष पूर्व के समर्थन से भी कहीं ज्यादा होने के कारण उन्हें अपने मिशन में हैट्रिक (निरंतर तीन बार) विजयी होने का गौरव प्राप्त होने की संभावना है सीएसडीएस सर्वेक्षण में बताया है कि 52 प्रतिशत मतदाताओं ने भाजपा के पक्ष में होकर भाजपा को सत्ता में लौटने के अवसर प्रदान किया है जो कि 2007 में 48 प्रतिशत था। श्री मोदी की व्यक्तिगत लोकप्रियता भी ज्यों की त्यों बनी है, जिसमें लगभग आधे उत्तरदाताओं ने- 49 प्रतिशत ने- उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए समर्थन दिया है जब मुख्यमंत्री पद का दावा करने की बात हुई तो उनके विरोधियों में से कोई भी दो अंकों के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाया। सच तो यह है कि इस सर्वेक्षण से यह एक बड़ा संदेश गया है कि मोदी की लोकप्रियता आज तक सबसे उच्च स्थान पर बनी हुई है। 2002 में, जब राज्य-व्यापी दंगों की पृष्ठभूमि में भाजपा के सत्ता में लौटने की बात आई थी तो मोदी को 37 प्रतिशत मतदाताओं ने ही मुख्यमंत्री पद के लिए चाहा था। परन्तु तब से, 2004 को छोड़कर जब उनकी लोकप्रियता घट कर 31 प्रतिशत पहुंची थी, उन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत किया है, 2012 में ऐसा कोई नेता नहीं है जो उनके कहीं आसपास भी पहुंच पाता है।

श्री नरेन्द्र मोदी का बढ़े ग्राफ के पीछे प्रमुख कारण यह है कि उनके महान नेतृत्व में राज्य ने तेजी से आर्थिक प्रगति की और जितने में आर्थिक संकेत होते है, उन सभी में अर्थव्यवस्था सुदृढ़ है। अधिकांश मतदाता गुजरात के विकास के लिए भाजपा को श्रेय देते है, यहां तक कि अधिकांश-गैर-भाजपा और गैर-कांग्रेसी मतदाता भी मोदी के शासन को विकासोन्मुखी मानते हैं। इसके उलट, गुजरात के अधिकांश मतदाता कांग्रेस नीत यूपीए सरकार को महंगाई की मार के लिए दोषी ठहराते है न कि श्री मोदी के शासन को।

भ्रष्टाचार के मामले में भी, यूपीए और राज्य सरकार दोनों को दोषी समझा

गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर सबसे लम्बे समय तक रहने वाले बने नरेन्द्र मोदी

श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात में 11 वर्षों तक सत्ता का कार्यभार संभालकर सबसे लम्बे समय तक मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया। परन्तु विगत वर्ष के विपरीत, जब राज्य सरकार ने शासन के 10 वर्षों का समारोह धूमधाम से मनाया था, इस बार कुछ ही दिन पहले आगामी चुनावों की तारीखों की घोषणा किए जाने के बाद आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण किसी प्रकार का समारोह आयोजित नहीं हो पा रहा है। श्री मोदी ने आज अपने ब्लाग में ''सबका साथ, सबका विकास : गुजरात में मेरी 11 वर्ष की यात्रा'' शीर्षक से अपने संदेश में कहा है- ''गुजरात के लोगों की सेवा में लगी मेरी 11 वर्ष की यात्रा स्मरणीय और अत्यंत संतोषजनक रही। मेरे लिए यह ज्ञानप्रद अनुभव रहा जो मेरे लिए अत्यंत सुखद रहा।'' अपने संदेश में श्री मोदी ने सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों, कार्यक्रमों और योजनाओं को स्पष्ट किया और इन्हें पूरे राज्य के विकास की भारी सफलता बताया। श्री मोदी ने गुजरात के विकास में 'नारी शक्ति' को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि ''गुजरात के विकास के पीछे हमारी नारी शक्ति रही है और कहा कि 2005 की चिरंजीवी योजना, 2006 की नारी गौरव नीति 2010 का मिशन मंगलम् का श्रेय राज्य की नारी शक्ति तो ही जाता है।'' श्री मोदी ने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में भव्य सफलता का दावा किया। उन्होंने कहा कि मेरी सदैव रही है कि हमारे शासन में प्राथमिक शिक्षा और विशेष रूप से कन्याओं की शिक्षा का क्षेत्र अपनी अमिट छाप छोड़े।''

जाता है, परन्तु केन्द्र इस मामले में कहीं ज्यादा खलनायक की भूमिका अदा करता है। प्रधानमंत्री पद पर श्री मनमोहन सिंह की परफोर्मेंस के मुकाबले मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए श्री मोदी की परफोर्मेंस पर लोग कहीं ज्यादा संतुष्ट है।

एक अन्य चुनाव-पूर्व सर्वेक्षण का आयोजन लेंस-ऑन-न्यूज ने किया। इस सर्वेक्षण में बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी की सम्पूर्ण वोटों का 50 प्रतिशत मिलने की संभावना है और वह गुजरात में आगामी चुनावों में 182 सीटों में से 133 सीटों पर कब्जा कर लेगी। इसके विपरीत, कांग्रेस अपना 38 प्रतिशत बनाए रखेगी, परन्तु उसे केवल 43 सीटें मिलेगी जिसका मतलब है कि 2007 में जीती सीटों से 16 सीटें कम मिलेंगी। इस सर्वेक्षण में यह निष्कर्ष 7,294 मतदाताओं से बातचीत कर निकाला गया।

इसमें कहा गया है कि भाजपा को एक प्रतिशत वोटों का लाभ प्राप्त होने की संभावना है, परन्तु 2007 की तुलना में 16 सीटें अधिक प्राप्त हो सकेंगी।■

गुजरात विधानसभा चुनाव 2007

पार्टी	सीटें लड़ी	जीतीं	जमानत जब्त	कुल मत	प्रतिशत मत
1. बीजेपी	182	117	2	10739972	49.12
2. बीएसपी	166	0	163	572540	2.62
3. सीपीआई	2	0	2	5472	0.03
4. सीपीएम	1	0	0	32567	0.15
5. आईएनसी	173	59	1	8309449	38.00
6. एनसीपी	10	3	4	230517	1.05

गुजरात विधानसभा चुनाव 2002

पार्टी	सीटें लड़ी	जीतीं	जमानत जब्त	कुल मत	प्रतिशत मत
1. बीजेपी	182	127	1	10194353	49.85
2. बीएसपी	34	0	34	66429	0.32
3. सीपीआई	1	0	1	3716	0.02
4. सीपीएम	1	0	0	30626	0.15
5. आईएनसी	180	51	0	8033104	39.28
6. एनसीपी	81	0	77	349021	1.71

गुजरात विधानसभा चुनाव 1998

पार्टी	सीटें लड़ी	जीतीं	जमानत जब्त	कुल मत	प्रतिशत मत
1. बीजेपी	182	117	3	7300826	44.81
2. बीएसपी	7	0	7	12742	0.08
3. सीपीआई	8	0	8	10292	0.06
4. सीपीएम	1	0	0	19665	0.12
5. आईएनसी	179	53	13	5677386	34.85
6. जेडी	91	4	83	429283	2.63
7. एसएपी	8	0	8	7512	0.05

मुस्लिमों ने भी किया मोदी का जमकर समर्थन

कांग्रेस और उनके 'सेक्युलरवादी' सहयोगी दलों ने मीडिया के कतिपय वर्गों के साथ मिलकर 2002 में हुई गोधरा घटनाओं के आधार पर गुजरात दंगों के आरोपों पर बार-बार जोर देकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को चुनाव में बार-बार शिकस्त मिलने के बावजूद भी इन्होंने दंगों के लिए गुजरात के मुख्य मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पर बड़ी बेशर्मी से आरोप लगाने से बाज नहीं आते रहे हैं लेकिन गुजरात के लोगों ने जब-जब भी उन्होंने खाई डालने की कोशिश की तब-तब गुजरात के लोगों ने हर बार कांग्रेस को खारिज कर उसे मात दी है। मुस्लिमों ने उनकी साम्प्रदायिक राजनीति का जम कर जवाब देते हुए उन्होंने खुल्लम-खुल्ला भाजपा में शामिल होना शुरू कर दिया और उन्हें श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व का समर्थन करने में जरा भी हिचक नहीं दिखाई। अभी कुछ वर्ष पहले तक, यह प्राय: कहा जाता था कि नरेन्द्र मोदी के पास मुस्लिम समुदाय के समर्थन में कोई भी आवाज उठाने वाला मुस्लिम नहीं है। आज नरेन्द्र मोदी के समर्थन में एक नहीं अनेक मुस्लिम खड़े हैं और वे इस समुदाय की व्यापक चिंताओं का समाधान करने में मोदी की गहन मदद करते हैं। मोदी से जुड़े जिन लोगों को नाम लिया जा सकता है, उनमें एक है आसिफ खान, जो कभी सोनिया के अत्यंत विश्वासप्रिय अहमद पटेल के संरक्षण में रहते थे और जिन्होंने भाजपा की शरण ले ली है(एक और व्यक्ति जफर सरेशवाला है जो व्यापारी हैं, जिन्होंने नरेन्द्र मोदी के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कई मानवाधिकार मामले दायर किए थे, एक और व्यक्ति अली सैयद है जो गुजरात के पूर्व पुलिस इंस्पेक्टर जनरल हुआ करते थे। सैयद को अहमदाबाद में विगत निगम चुनावों में मेयर के पद पर उम्मीदवार बनाया गया था, परन्तु वे हार गए थे। अब वह राज्य वक़्फ़ बोर्ड के अध्यक्ष हैं। एक और महत्वपूर्ण चेहरा है सूफी संत बाबा महबूब अली, जो भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। वह हज कमेटी के भी प्रमुख हैं। ■

जीवन का ध्येय

-दीनदयाल उपाध्याय

एकात्ममानव दर्शन के प्रणेता व भारतीय जनसंघ के पूर्व अध्यक्ष पं. दीनदयाल उपाध्याय समय-समय पर लेख लिखकर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते थे। पांचजन्य (भाद्रपद कृष्ण 9, वि.सं. 2006) में लिखे इस लेख में उन्होंने जीवन का ध्येय क्या हो, इस पर विस्तार से प्रकाश डाला था। हम इस लेख की महत्ता को देखते हुए इसे यहां प्रकाशित कर रहे हैं:-

विश्व का प्रत्येक प्राणी सतत् इस बात का प्रयत्न करता रहता है कि उसका अस्तित्व बना रहे, वह जीवित रहे। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वह दूसरे अनेक प्राणियों को अस्तित्वहीन करने का प्रयत्न करता रहता है तथा स्वयं उसको अस्तित्वहीन करनेवाली शक्तियों से निरंतर

अपनी रक्षा करता रहता है। विनाश और रक्षा के इन प्रयत्नों की समष्टि का ही नाम जीवन है। इन प्रयत्नों की भिन्नता ही भिन्न-भिन्न प्रकार के जीवनों का कारण है तथा इनकी सफलता या असफलता ही विभिन्न प्राणियों के विकास या विकार का मापदंड है। मानव भी इस नियम का अपवाद नहीं है। आदि मानव की सृष्टि और तब से अब तक का इतिहास इन प्रयत्नों का ही इतिहास है। किंतु मनुष्य विश्व के प्राणियों से अधिक विकसित है उसका अस्तित्व केवल प्राथमिक भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति पर ही निभर नहीं करता किंतु उसके जीवन में भौतिकता के साथ-साथ आधिभौतिक एवं आध्यात्मिक तत्त्वों का भी समावेश होता है। मनुष्य के जीवन का ध्येय श्वासोच्छवास तथा श्वासोच्छवास की क्रिया को बनाए रखना ही नहीं है, किंतु इससे भिन्न है। वह तो श्वासोच्छवास मात्र जीवन को साधन मानता है, साध्य नहीं। उसका साध्य तो उपनिषदों के शब्दों में है-

'आत्मा वा रे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मन्तव्यो निर्दिध्यासितव्यः।'

वह आत्मा की अनुभूति करना चाहता है, उसे समझना चाहता है, अपनी संपूर्ण क्रियाओं को उस अनुभूति के प्रति लगाता है।

हमारी प्रेरक शक्ति

यह आत्मा क्या है जिसके लिए मानव इतना तड़पता है? इस संबंध में अनेक मतभेद हैं और इन्हीं मतभेदों के कारण विश्व में अनेक संप्रदायों की सृष्टि हुई है। अनेक मनीषियों ने इस आत्मा को विश्व का आदि कारण, उसका कर्ता, धर्ता एवं हर्ता, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी परब्रह्म परमेश्वर को ही माना है। उनका कथन है कि वही एकमेव शक्ति है। जो संपूर्ण विश्व को चला रही है तथा प्रत्येक प्राणी उस ओर ही बढ़ने का प्रयत्न कर रहा है, वह उसी में मिल जाना चाहता है और इसलिए मानव का प्रयत्न उस परब्रह्म का साक्षात्कार ही है। उस परब्रह्म में ही पूर्णता होने के कारण 'सत्यं शिवं और सुन्दरं' की पूर्णाभिव्यक्ति होने के कारण ही मनुष्य इन गुणों की ओर आकर्षित होता है तथा जीवन के हर क्षेत्र में इन गुणों की आंशिक अनुभूति करता हुआ पूर्ण साक्षात्कार के लिए प्रयत्नशील रहता है। कुछ विद्वान् इस अदृश्य शक्ति में विश्वास न करते हुए केवल हृदय जगत् में ही विश्वास रखते हैं तथा उसमें भी मानव के विकास को (उसके सुख-साधन-संपन्न जीवन को) ही परम लक्ष्य मानकर सुख की प्राप्ति के प्रयत्नों को ही मानव जीवन का एकमेव कर्तव्य समझते हैं। उनके विचारों में ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है अपितु यदि गहराई से देखा जाए तो ज्ञात होगा कि मानव को एकता की अनुभूति

तथा उसको सुखमय बनाने की इच्छा को प्रेरकशक्ति निश्चित ही दृश्य सृष्टि से भिन्न कोई सूक्ष्म तत्त्व है जो इस दृश्य जगत् को परिव्याप्त किए हुए प्रत्येक प्राणी के अंत:करण में संपूर्णता को, एकात्मता की भावना उत्पन्न करता है। उस शक्ति को आप चाहे जो नाम दें किंतु यह निश्चित है कि उसकी ओर प्रत्येक मानव अग्रसर है तथा मानवता के कल्याण की भावना किसी स्वार्थ का परिणाम नहीं किंतु आत्मानुभूति की इच्छा का परिणाम है। अज्ञानवश मानव आत्मा के स्वरूप को संकुचित करने का प्रयत्न करता है किंतु सत्य का ज्ञान सतत् अज्ञान पटल को भेदने के लिए प्रयत्नशील होता है।

अपनी प्रतिमा का विकास

संपूर्ण सृष्टि को एकात्मता के साक्षात्कार का ध्येय सम्मुख रखते हुए भी मानव अपनी प्रकृति के अनुसार ही उसकी ओर अग्रसर होता है। उसी प्रकार संसार के भिन्न-भिन्न भागों में रहनेवाला मानव भी संपूर्ण मानव को आंतरिक एकता की भावना रखते हुए तथा उसकी पूर्णानुभूति की इच्छा रखते हुए भी प्रकृति की साधनों एवं उनको अपने नियंत्रण में करके आगे बढ़ने के प्रयत्नों में अपनी एक विशिष्ट दिशा निश्चित कर लेता है, उसकी कुछ विशेषताएँ हो जाती हैं, उसको अपनी निजी प्रतिभा का विकास हो जाता है। यद्यपि संपूर्ण पृथ्वी एक है किंतु उसके ऊपर स्थित पहाड़, पर्वत, सागर और वन उसके भिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की जलवायु और वनस्पति अपना प्रभाव उस प्रदेश के मानव पर डाले बिना नहीं रहते तथा उस विशिष्ट भू-भाग के मनुष्य पूर्णानुभूति के प्रयत्नों में अपना विकास निश्चित दिशा में करते हैं। उनका अपना एक निजी स्वत्व हो जाता है जो कि उसी प्रकार की दूसरी इकाइयों से उसी प्रकार

संपूर्ण सृष्टि को एकात्मता के साक्षात्कार का ध्येय सम्मुख रखते हुए भी मानव अपनी प्रकृति के अनुसार ही उसकी ओर अग्रसर होता है। उसी प्रकार संसार के भिन्न-भिन्न भागों में रहनेवाला मानव भी संपूर्ण मानव को आंतरिक एकता की भावना रखते हुए तथा उसकी पूर्णानुभूति की इच्छा रखते हुए भी प्रकृति की साधनों एवं उनको अपने नियंत्रण में करके आगे बढ़ने के प्रयत्नों में अपनी एक विशिष्ट दिशा निश्चित कर लेता है, उसकी कुछ विशेषताएँ हो जाती हैं, उसको अपनी निजी प्रतिभा का विकास हो जाता है।

भिन्न होता है जैसेकि एक ही सेना के विभिन्न अंग। आधुनिक युद्ध में जल, थल और वायु सेना जिस प्रकार अपनी-अपनी पद्धति से एक ही युद्ध को जीतने का प्रयत्न करती हैं उसी प्रकार संसार के भिन्न-भिन्न राष्ट्र एक ही मानवता की अनुभूति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। जल, थल और वायु सेना में कार्य करने में सैनिकों को अपनी विशेष प्रतिभा का विकास होता है तथा वे अपनी निजी पद्धति से शत्रु को पराजित करने का प्रयत्न करते रहते हैं। तीनों सेनाओं में सामंजस्य रहना तो अच्छा है किंतु यदि किसी सेना के सैनिक अपनी पद्धति को ही सत्य मानकर दूसरी सेना के सैनिकों पर प्रभाव जमाने का प्रयत्न करें अथवा उसकी प्रतिभा को नष्ट करना चाहें तो उनका यह प्रयत्न अंतिम ध्येय की पूर्ति में बाधक होगा तथा आक्रमित सेना के सैनिकों का कर्तव्य होगा कि वे आक्रमणकारी सैनिकों से ही प्रथम युद्ध करके उनकी बुद्धि को ठिकाने पर ला दें। इसी प्रकार यदि किसी सेना के विशेष प्रभाव को देखकर अथवा किसी विशेष क्षेत्र में उनकी विजयों को देखकर अथवा आक्रमणकारी सेना की सामर्थ्य का अनुभव करते हुए कोई सेना अपनी पद्धति, अपने प्रयत्न तथा अपनी प्रतिभा को तिलांजलि देकर उस दूसरी सेना की विशेषताओं को और उसमें भी विशेषकर उसके बाह्य स्वरूप को अपनाने का प्रयत्न करती है तो वह तो स्वतरू नष्ट हो ही जाएगी अपितु मानव की अंतिम विजय में भी अपना दायित्व नहीं निभा पाएगी।

आक्रमण वृत्ति

विश्व के अनेक राष्ट्रों का इतिहास उपर्युक्त उदाहरण की भावनाएँ ही परिलक्षित करता है। प्रत्येक राष्ट्र अपनी विशिष्ट पद्धति को सत्य समझने लगता है तथा अपने को ही एकमेव प्रतिभावान् मानकर दूसरे राष्ट्रों पर अपनी पद्धतियों को लादने का प्रयत्न करता है। यदि यह प्रयत्न शांतिमय होता तो भी कुछ बात नहीं किंतु वह जबरदस्ती अपने सत्य को दूसरों के गले उतारना चाहता है। मानव के सुख और वैभव को भी वह अपने राष्ट्र के सुख और वैभव तक ही सीमित करके दूसरे राष्ट्रों के सुख और शांति को नष्ट करता है, उसके प्राकृतिक विकास में बाधा डालता है। फलत: एक राष्ट्र दूसरे पर विजय प्राप्त कर लेता है और उसे गुलाम बना लेता है। परतंत्र राष्ट्र का जीवन प्रवाहरुद्ध हो जाता है। उसके घटक किसी-न-किसी प्रकार श्वासोच्छवास तो करते रहते हैं किंतु वे

अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव नहीं कर पाते। भौतिक दृष्टि से सुखोपभोग करनेवाले व्यक्ति भी परतंत्रता का ताप अनुभव करते रहते हैं क्योंकि उनका आत्मसम्मान नष्ट हो जाता है, उनकी भावनाओं पर ठेस पहुँचती है तथा उनकी प्रतिभा कुंठित होने लगती है, उनकी आत्मानुभूति का मार्ग बंद हो जाता है। युगयुगों से उनकी प्रतिभा ने प्रस्फुटित होकर जिन विशेष वस्तुओं का निर्माण किया होता है, उसकी अवमानना होने लगती है तथा उनके विनाश का पथ प्रशस्त हो जाता है। उस राष्ट्र की भाषा, संस्कृति, साहित्य और परंपरा नष्ट होने लगती है, उसके महापुरुषों के प्रति अश्रद्धा निर्माण की जाती है तथा उसके नैतिक मापदंडों को निम्नतर ठहराया जाता है। उसके जीवन की पद्धतियाँ विदेशी पद्धतियों से आक्रांत हो जाती हैं तथा विदेशी आदर्श उसके अपने आदर्शों का स्थान ले लेते हैं। फलत: उस राष्ट्र के व्यक्तियों की दशा विक्षिप्त व्यक्ति के समान हो जाती हैय अपनी प्रकृति, स्वभाव और प्रतिभा के अनुसार कार्य करने की सुविधा न रहने के कारण वे प्रगति के पथ पर अग्रसर होने से ही वंचित नहीं रह जाते अपितु पतन की ओर भी अग्रसर हो जाते हैं।

आज यदि दिल्ली का शासनकर्ता अंग्रेज के स्थान पर हममें से ही एक, हमारे ही रक्त और माँस का एक अंश हो गया है तो हमको इसका हर्ष है, संतोष है, किंतु हम चाहते हैं कि उनकी भावनाएँ और कामनाएँ भी हमारी भावनाएँ और कामनाएँ हों। जिस देश की मिट्टी से उसका शरीर बना है, उसके प्रत्येक रजकण का इतिहास उसके शरीर के कण-कण से प्रतिध्वनित होना चाहिए, तीस कोटि के हृदयों को समष्टिगत भावनाओं से उसका हृदय उद्वेलित होना चाहिए तथा उनके जीवन के विकासक अनुकूल, उनकी प्रकृति और स्वभाव अनुसार तथा उनकी भावनाओं और कामनाओं के अनुरूप पद्धतियों की सृष्टि उसके द्वारा होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो हमको कहना होगा कि अभी भी स्वतंत्रता की लड़ाई बाकी है।

हमारी स्वतंत्रता

ऐसी दशा में उस राष्ट्र के घटकों का प्रथम कर्तव्य हो जाता है कि विजेता राष्ट्र के प्रभुत्व को नष्ट करके अपने राष्ट्र को स्वतंत्र किया जाए। उस राष्ट्र की संपूर्ण शक्ति विदेशी राष्ट्र के प्रति विद्रोह की भावना लेकर खड़ी हो जाती है और अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार अवसर प्राप्त होने पर स्वतंत्रता को प्राप्त करती है। विश्व के इस नियम के अनुसार भारतवर्ष ने भी अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध बगावत का झंडा खड़ा किया और अंत में एक राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ही ली।

15 अगस्त, 1947 को हमने एक मोरचा जीत लिया। हमारे देश से अंग्रेजी राज्य विदा हो गया। उस राज्य के कारण हमारी प्रतिभा के विकास में जो बाधाएँ उपस्थित की जा रही थीं, उनका कारण हट गया, हम अपना विकास करने के लिए स्वतंत्र हो गए। अपनी आत्मानुभूति का मार्ग खुल गया। किंतु अभी भी मानव की प्रगति में हमको सहायता करनी है। मानव द्वारा छेड़े गए युद्ध में जिन-जिन शस्त्रास्त्रों का प्रयोग हमने अब तक किया है, जिनके चलाने में हम निपुण हैं तथा जिन पर पिछली सहस्राब्दियों में जंग लग गई थी उन्हें पुन: तीक्ष्ण करना है तथा अपने युद्ध कौशल का परिचय देकर मानव को विजय बनाना है। आज यदि हमारे मन में उन पद्धतियों के विषय में ही मोह पैदा हो जाए, जिनके पुरस्कर्ताओं से हम अब तक लड़ते रहे हैं तो यही कहना होगा कि हम न तो स्वतंत्रता का सच्चा स्वरूप समझ पाए हैं और न अपने जीवन के ध्येय को ही पहचान पाए हैं। हमारी आत्मा ने अंग्रेजी राज्य के प्रति विद्रोह केवल इसलिए नहीं किया कि दिल्ली में बैठकर राज्य करनेवाला एक अंग्रेज था, अपितु इसलिए भी कि हमारे दिन-प्रतिदिन के जीवन में हमारे जीवन की गति में विदेशी पद्धतियाँ और रीति-रिवाज विदेशी दृष्टिकोण और आदर्श अडंगा लगा रहे थे, हमारे संपूर्ण वातावरण को दूषित कर रहे थे, हमारे लिए साँस लेना भी दूभर हो गया था।

आज यदि दिल्ली का शासनकर्ता अंग्रेज के स्थान पर हममें से ही एक, हमारे ही रक्त और माँस का एक अंश हो गया है तो हमको इसका हर्ष है, संतोष है, किंतु हम चाहते हैं कि उनकी भावनाएँ और कामनाएँ भी हमारी भावनाएँ और कामनाएँ हों। जिस देश की मिट्टी से उसका शरीर बना है, उसके प्रत्येक रजकण का इतिहास उसके शरीर के कण-कण से प्रतिध्वनित होना चाहिए, तीस कोटि के हृदयों को समष्टिगत भावनाओं से उसका हृदय उद्वेलित होना चाहिए तथा उनके जीवन के विकासक अनुकूल, उनकी प्रकृति और स्वभाव अनुसार तथा उनकी भावनाओं और कामनाओं के अनुरूप पद्धतियों की सृष्टि उसके द्वारा होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो हमको कहना होगा कि अभी भी स्वतंत्रता की लड़ाई बाकी है। अभी हम अपनी आत्मानुभूति में आनेवाली बाधाओं को दूर नहीं कर पाए हैं।

सब प्रकार स्वतंत्र हों

अंग्रेजी राज्य के चले जाने के बाद आवश्यक है कि हमारा देश आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में भी स्वतंत्रता का अनुभव करें। जब तक भारतवर्ष आर्थिक दृष्टि से परमुखापेक्षी है तथा भारत को तीस कोटि संतान की आर्थिक उन्नति का समान अवसर प्राप्त नहीं है, जब तक उनकी उन्नति के द्वार खुले नहीं हैं तथा उसके साधन प्रस्तुत नहीं हैं, तब तक भारतवर्ष विश्व की प्रगति में कदापि सहायक नहीं हो सकता। न तो वह जीवन के सत्य का साक्षात्कार कर सकेगा और न मानव की स्वतंत्रता का ही।

आर्थिक स्वाधीनता के साथ-साथ सामाजिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता की भी आवश्यकता है। आत्मानुभूति के प्रयत्नों में जिन सामाजिक व्यवस्थाओं एवं पद्धतियों की राष्ट्र अपनी सहायता के लिए सृष्टि करता है अथवा जिन रीति-रिवाजों में उसकी आत्मा की अभिव्यक्ति होती है, वे ही यदि कालावपात से उसके मार्ग में बाधक होकर उसके ऊपर भार रूप हो जाएँ तो उनसे मुक्ति पाना भी प्रत्येक राष्ट्र के लिए आवश्यक है। यात्रा की एक मंजिल में जो साधन उपयोगी सिद्ध हुए हैं वे दूसरी मंजिल में भी उपयोगी सिद्ध होंगे यह आवश्यक नहीं। साधन तो प्रत्येक मंजिल के अनुरूप ही चाहिए तथा इस प्रकार प्रयाण करते हुए प्राचीन साधनों का मोह परतंत्रता का ही कारण हो सकता है क्योंकि स्वतंत्रता केवल उन तंत्रों का समष्टिगत नाम है जो स्वानुभूति में सहायक होते हैं।

सांस्कृतिक स्वतंत्रता

राष्ट्र की सांस्कृतिक स्वतंत्रता तो अत्यंत महत्त्व की है, क्योंकि संस्कृति ही राष्ट्र के संपूर्ण शरीर में प्राणों के समान संचार करती है। प्रकृति के तत्त्वों पर विलय पाने के प्रयत्न में तथा मानवानुभूति की कल्पना में मानव जिस जीवन दृष्टि की रचना करता है वह उसकी संस्कृति है। संस्कृति कभी गतिहीन नहीं होती अपितु वह निरंतर गतिशील फिर भी उसका अपना एक अस्तित्व है नदी के प्रवाह की भाँति निरंतर गतिशील होते हुए भी वह अपनी निजी विशेषताएँ रखती हैं जो उस सांस्कृतिक दृष्टिकोण को उत्पन्न करनेवाले समाज के संस्कारों में तथा उस सांस्कृतिक भावना से जन्य राष्ट्र के साहित्य, कला, दर्शन, स्मृति शास्त्र, समाज रचना इतिहास एवं सभ्यता के विभिन्न अंग अंगों में व्यक्त होती हैं। परतंत्रता के काल में इन सब पर प्रभाव पड़ जाता है तथा स्वाभाविक प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। आज स्वतंत्र होने पर आवश्यक है कि हमारे प्रवाह की संपूर्ण बाधाएँ दूर हों तथा हम अपनी प्रतिभा अनुरूप राष्ट्र के संपूर्ण क्षेत्रों में विकास कर सकें। राष्ट्र भक्ति की भावना को निर्माण करने और उसको साकार स्वरूप देने का श्रेय भी राष्ट्र की संस्कृति को ही है तथा वही राष्ट्र की संकुचित सीमाओं को तोड़कर मानव की एकात्मता का अनुभव कराती है। अत: संस्कृति की स्वतंत्रता परमावश्यक है। बिना उसके राष्ट्र की स्वतंत्रता निरर्थक ही नहीं, टिकाऊ भी नहीं रह सकेगी।

स्वार्थ का साधन नहीं

आज अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता का उत्सव मनाते समय हम स्वतंत्रता के इन मूल्यों को समझें। स्वतंत्रता की कुछ व्यक्ति समूह के स्वार्थ सिद्धि का साधन बनाना, फिर वह व्यक्ति समूह तीस करोड़ का ही क्यों न हो, स्वतंत्रता को उसके महान् आसन से गिराकर धूल में मिलाना होगा। इस प्रकार के दृष्टिकोण से कार्य करने पर न तो स्वतंत्रता को हम अनुभूति ही कर पाएँगे और न हम विश्व को ही कुछ सेवा कर पाएँगे। अपितु इस प्रकार का स्वार्थी और अहंकारी भाव लेकर कार्य करने पर हम उसी इतिहास की पुनरावृत्ति करेंगे जो कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर प्रभाव जमाने में निर्माण करता है।

आज स्वतंत्र होने पर आवश्यक है कि हमारे प्रवाह की संपूर्ण बाधाएँ दूर हों तथा हम अपनी प्रतिभा अनुरूप राष्ट्र के संपूर्ण क्षेत्रों में विकास कर सकें। राष्ट्र भक्ति की भावना को निर्माण करने और उसको साकार स्वरूप देने का श्रेय भी राष्ट्र की संस्कृति को ही है तथा वही राष्ट्र की संकुचित सीमाओं को तोड़कर मानव की एकात्मता का अनुभव कराती है। अत: संस्कृति की स्वतंत्रता परमावश्यक है। बिना उसके राष्ट्र की स्वतंत्रता निरर्थक ही नहीं, टिकाऊ भी नहीं रह सकेगी।

यहाँ पात्र भिन्न होंगे, वे एक ही राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर प्रभाव जमाने में निर्माण करता है। यहाँ पात्र भिन्न होंगे, वे एक ही राष्ट्र के घटक होंगे, पास-पास रहनेवाले पड़ोसी होंगे और इसलिए उनके कृत्य और भी भयंकर हो जाते हैं तथा उसका परिणाम भी सर्वव्यापी विनाश हो सकता है। किंतु हमारा विश्वास है कि राष्ट्र की जीवनदायिनी शक्ति अपने सच्चे स्वरूप और कार्य को समझेगी तथा विनाश के स्थान पर विकास के मार्ग पर अग्रसर होती हुई भारत की तीस कोटि संतान अपने परम लक्ष्य परब्रह्म की प्राप्ति तथा विश्वात्मा की अनुभूति कराएगी। ■

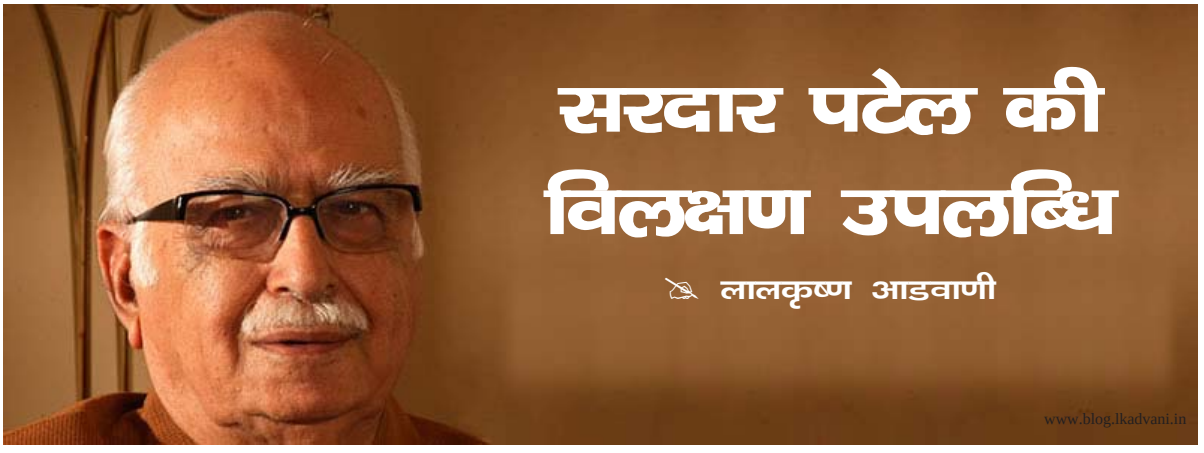

सरदार पटेल की विलक्षण उपलब्धि

लालकृष्ण आडवाणी

हाल ही में एक अत्यंत रोचक पुस्तक: ''इण्डियन समर: दि सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ दि एण्ड ऑफ एन एम्पायर'' देखने को मिली। इसकी लेखिका एक जर्मन महिला हैं जिनका नाम है आलेक्स फॉन टूनसेलमान। यह उनकी पहली पुस्तक है।

पुरस्कार विजेता इतिहासकार विलियम डलरिम्पल ने इस पुस्तक को 'एक श्रेष्ठ कृति' और ''स्वतंत्रता तथा भारत व पाकिस्तान विभाजन पर मेरे द्वारा पढ़ी गई निस्संदेह उत्तम पुस्तक'' के रुप में वर्णित किया है।

जब भारत पर अंग्रेजी राज था तब देश एक राजनीतिक इकाई नहीं था। इसके दो मुख्य घटक थे: पहला, ब्रिटिश भारत, दूसरा, रियासतों वाला भारत। रियासतों वाले भारत में 564 रियासतें थी।

वी.पी. मेनन की पुस्तक: ''दि स्टोरी ऑफ इंटिग्रेशन ऑफ दि इण्डियन स्टेट्स'' में प्रसिद्ध पत्रकार एम.वी. कामथ ने लेखक के बारे में यह टिप्पणी की है:

"जबकि सभी रियासतों-जैसाकि उन्हें पुकारा जाता था-को भारत संघ में विलय कराने का श्रेय सरदार को जाता है, लेकिन वह भी ऐसा इसलिए कर पाए कि उन्हें एक ऐसे व्यक्ति का उदार समर्थन मिला जो राजाओं की मानसिकता और मनोविज्ञान से भलीभांति परिचित थे, और यह व्यक्ति कौन था? यह थे वापल पनगुन्नी मेनन-वी.पी. मेनन के नाम से उन्हें जल्दी ही पहचाना जाने लगा।''

"वीपी के प्रारम्भिक जीवन के बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। एक ऐसा व्यक्ति जो सभी व्यावहारिक रुप से पहले, अंतिम वायसराय लार्ड लुईस माउंटबेटन और बाद में,, भारत के लौह पुरुष महान सरदार वल्लभ भाई पटेल के खासमखास बने, ने स्वयं गुमनामी में जाने से पहले अपने बारे में बहुत कम जानकारी छोड़ी। यदि वह सत्ता के माध्यम से कुछ भी पाना चाहते तो जो मांगते मिल जाता।''

जब भारत पर अंग्रेजी राज था तब देश एक राजनीतिक इकाई नहीं था। इसके दो मुख्य घटक थे: पहला, ब्रिटिश भारत, दूसरा, रियासतों वाला भारत। रियासतों वाले भारत में 564 रियासतें थी।

यह पुस्तक वी.पी. मेनन द्वारा भारतीय इतिहास के इस चरण पर लिखे गए दो विशाल खण्डों में से पहली (1955) है। दूसरी पुस्तक (1957) का शीर्षक है: ''दि ट्रांसफर ऑफ पॉवर इन इण्डिया।''

जिस पुस्तक ने मुझे आज का ब्लॉग लिखने हेतु बाध्य किया, उसमें रियासती राज्यों के मुद्दे पर 'ए फुल बास्केट ऑफ ऐप्पल्स' शीर्षक वाला अध्याय है। इस अध्याय की शुरुआत इस प्रकार है:

"18 जुलाई को राजा ने लंदन में इण्डिया इंडिपेंडेंस एक्ट पर हस्ताक्षर किए और माउंटबेटन दम्पति ने अपने विवाह की रजत जयंती दिल्ली में मनाई, पच्चीस वर्ष बाद उसी शहर में जहां दोनों की सगाई हुई थी।''

यह पुस्तक कहती है कि रियासती राज्यों के बारे में ब्रिटिश सरकार के इरादे"अटली द्वारा जानबूझकर अस्पष्ट छोड़ दिए गए थे।'' माउंटबेटन से यह अपेक्षा थी कि वह रियासतों की ब्रिटिश भारत से उनके भविष्य के रिश्ते रखने में सही दृष्टिकोण अपनाने हेतु सहायता करेंगे। नए वायसराय को भी यह बता दिया गया था कि 'जिन राज्यों में राजनीतिक प्रक्रिया धीमी थी, के शासकों को वे अधिक लोकतांत्रिक सरकार के किसी भी रूप हेतु तैयार

करें।"

माउन्टबेटन ने इसका अर्थ यह लगाया कि वह प्रत्येक राजवाड़े पर दबाव बना सकें कि वह भारत या पाकिस्तान के साथ जाने हेतु अपनी जनता के बहुमत के अनुरूप निर्णय करें। उन्होंने पटेल को सहायता करना स्वीकार किया और 15 अगस्त से पहले 'ए फुल बास्केट ऑफ ऐपल्स' देने का वायदा किया।

9 जुलाई को स्टेट्स के प्रतिनिधि अपनी प्रारम्भिक स्थिति के बारे में मिले। टुनसेलमान के मुताबिक अधिकांश राज्य भारत के साथ मिलना चाहते थे। "लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्यों में से चार-हैदराबाद, कश्मीर, भोपाल और त्रावनकोर-स्वतंत्र राष्ट्र बनना चाहते थे। इनमें से प्रत्येक राज्य की अपनी अनोखी समस्याएं थीं। हैदराबाद का निजाम दुनिया में सर्वाधिक अमीर आदमी था: वह मुस्लिम था,और उसकी प्रजा अधिकांश हिन्दू। उसकी रियासत बड़ी थी और ऐसी अफवाहें थीं कि फ्रांस व अमेरिका दोनों ही उसको मान्यता देने को तैयार थे। कश्मीर के महाराजा हिन्दू थे और उनकी प्रजा अधिकांशतया मुस्लिम थी। उनकी रियासत हैदराबाद से भी बड़ी थी परन्तु व्यापार मार्गों और औद्योगिक संभावनाओं के अभाव के चलते काफी सीमित थी। भोपाल के नवाब एक योग्य और महत्वाकांक्षी रजवाड़े थे और जिन्ना के सलाहकारों में से एक थे: उनके दुर्भाग्य से उनकी रियासत हिन्दूबहुल थी और वह भारत के एकदम बीचोंबीच थी, पाकिस्तान के साथ संभावित सीमा से 500 मील से ज्यादा दूर। हाल ही में त्रावनकोर में यूरेनियम भण्डार पाए गए, जिससे स्थिति ने अत्यधिक अंतर्राष्ट्रीय दिलचस्पी बढ़ा दी।''

इस समूचे प्रकरण में मुस्लिम लीग की रणनीति इस पर केंद्रित थी कि अधिक से अधिक रजवाड़े भारत में मिलने से इंकार कर दें। जिन्ना यह देखने के काफी इच्छुक थे कि नेहरु और पटेल को "घुन लगा हुआ भारत मिले जो उनके घुन लगे पाकिस्तान'' के साथ चल सके। लेकिन सरदार पटेल, लार्ड माउंटबेटन और वी.पी. मेनन ने एक ताल में काम करते हुए ऐसे सभी षड्यंत्रों को विफल किया।

इस महत्वपूर्ण अध्याय की अंतिम पंक्तियां इस जोड़ी की उपलब्धि के प्रति एक महान आदरांजलि है। ऑलेक्स फॉन टुनेसलेमान लिखती हैं:

"माउंटबेटन की तरकीबों या पटेल के तरीकों के बारे में चाहे जो कहा जाए, उनकी उपलब्धि उल्लेखनीय रहेगी। और एक वर्ष के भीतर ही, इन दोनों के बारे में तर्क दिया जा सकता है कि इन दोनों ने 90 वर्ष के ब्रिटिश राज, मुगलशासन के 180 वर्षों या अशोक अथवा मौर्या शासकों के 130 वर्षों की तुलना में एक विशाल भारत, ज्यादा संगठित भारत हासिल किया।''

जो जर्मन महिला ने जो अर्थपूर्ण ढंग से लिखा है उसकी पुष्टि वी.पी. मेनन द्वारा दि स्टोरी ऑफ इंटिग्रेशन ऑफ दि इण्डियन स्टेट्स' के 612 पृष्ठों में तथ्यों और आंकड़ों से इस प्रकार की है।

"564 भारतीय राज्य पांचवां हिस्सा या लगभग आधा देश बनाते हैं: कुछ बड़े स्टेट्स थे, कुछ केवल जागीरें। जब भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान एक पृथक देश बना तब भारत का 364,737 वर्ग मील और 81.5 मिलियन जनसंख्या से हाथ धोना पड़ा लेकिन स्टेट्स का भारत में एकीकरण होने से भारत को लगभग 500,000 वर्ग मील और 86.5 मिलियन जनसंख्या जुड़ी जिससे, भारत की पर्याप्त क्षतिपूर्ति हुई।"

स्टेट्स के एकीकरण सम्बंधी अपनी पुस्तक की प्रस्तावना में वी.पी. मेनन लिखते हैं: यह पुस्तक स्वर्गीय सरदार वल्लभभाई पटेल को किए गए वायदे की आंशिक पूर्ति है। यह उनकी तीव्र इच्छा थी कि मैं दो पुस्तकें लिखूं, जिसमें से एक में उन घटनाओं का वर्णन हो जिनके चलते सत्ता का हस्तांतरण हुआ और दूसरी भारतीय स्टेट्स के एकीकरण से सम्बन्धित हो।

टेलपीस (पश्च्यलेख)

30 अक्टूबर, 2012 को सरदार पटेल की जयंती की पूर्व संध्या पर 'पायनियर' ने एक समाचार प्रकाशित किया कि कैसे प्रधानमंत्री नेहरु हैदराबाद की मुक्ति के सरदार की योजना को असफल करना चाहते थे।

समाचार इस प्रकार है:

"तत्कालीन उपप्रधानमंत्री और भारत के गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल जिनकी 137वीं जयंती 31अक्टूबर को है, को तब के प्रधानमंत्री पण्डित जवाहरलाल नेहरु द्वारा एक केबिनेट मीटिंग के दौरान अपमानित और लांछित किया गया। "आप एक पूर्णतया साम्प्रदायिक हो और मैं तुम्हारे सुझावों और प्रस्तावों के साथ कभी पार्टी नहीं बन सकता''-नेहरु एक महत्वपूर्ण केबिनेट बैठक में सरदार पटेल पर चिल्लाए जिसमें निजाम की निजी सेना-रजाकारों के चंगुल से, सेना की कार्रवाई से हैदराबाद की मुक्ति पर विचार हो रहा था।

हतप्रभ सरदार पटेल ने मेज पर से अपने पेपर इकट्ठे किए और धीरे-धीरे चलते हुऐ कैबिनेट कक्ष से बाहर चले गए। यह अंतिम अवसर था जब पटेल ने कैबिनेट बैठक में भाग लिया। 1947 बैच के आईएस अधिकारी एम के नायर ने अपने संस्मरण "विद नो इल फीलिंग टू एनीबॉडी'' में लिखा है कि "उन्होंने

तब से नेहरु से बोलना भी बंद कर दिया।''

हालांकि नायर ने उपरोक्त वर्णित कैबिनेट बैठक की सही तिथि नहीं लिखी है, परन्तु यह हैदराबाद मुक्ति के लिए चलाए गए भारतीय सेना के अभियान ऑपरेशन पोलो, जो 13 सितम्बर, 1948 को शुरू होकर 18 सितम्बर को समाप्त हुआ, के पूर्ववर्ती सप्ताहों में हुई होगी।

जबकि सरदार पटेल 2,00,000 रजाकारों के बलात्कार और उत्पात से हैदराबाद को मुक्त कराने के लिए सेना की सीधी कार्रवाई चाहते थे, उधर नेहरू संयुक्त राष्ट्र के विकल्प को प्राथमिकता दे रहे थे।

नायर लिखते हैं कि सरदार पटेल के प्रति नेहरु की निजी घृणा 15 सितम्बर, 1950 को उस दिन और खुलकर सामने आई जिस दिन सरदार ने बॉम्बे (अब मुंबई) में अंतिम सांस ली। ''सरदार पटेल की मृत्यु का समाचार पाने के तुरंत बाद नेहरु ने राज्यों के मंत्रालय को दो नोट भेजे, इनमें से एक में नेहरु ने मेनन को लिखा कि सरदार पटेल द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली के कडिल्लक (Cadillac) कार को उनके कार्यालय को वापस भेज दिया जाए।''

दूसरा नोट क्षुब्ध कर देने वाला था। नेहरु चाहते थे कि सरकार के जो सचिव सरदार पटेल की अंतिम क्रिया में भाग लेने के इच्छुक थे, वे अपने निजी खर्चे पर ही जाएं।

"लेकिन मेनन ने सभी सचिवों की बैठक बुलाई और जो अंतिम क्रिया में जाना चाहते थे, की सूची मांगी। नेहरु द्वारा भेजे गए 'नोट' का उन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया। जिन लोगों ने सरदार की अंतिम यात्रा में जाने की इच्छा व्यक्त की थी उनके हवाई यात्रा के टिकट का पूरा खर्चा मेनन ने चुकाया।''■

मतदान के बाद आयोजित हि.प्र. भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक

भाजपा पुनः सत्ता संभालने को तैयार : धूमल

हिमाचल प्रदेश भाजपा ने 19 नवम्बर को शिमला में अपनी प्रदेश कार्यसमिति की एक दिवसीय बैठक आयोजित कर राज्य विधानसभा के लिए 4 नवम्बर को हुए मतदान की जमीनी यथार्थताओं पर विचार किया। चुनाव में लड़ने वाले सभी भाजपा प्रत्याशियों (एक को छोड़कर), भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्री सतपाल सत्ती, मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल और पदाधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया। इस अवसर पर सांसद श्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे। एक-एक कर सभी प्रत्याशियों ने मतदान सम्बन्धी अपना आकलन प्रस्तुत किया और उनमें से ऐसे प्रत्याशियों का भारी बहुमत था जिन्हें विजय प्राप्त करने की उम्मीद थी। बैठक के बाद पार्टी पूरे विश्वास से परिपूर्ण थी कि वह विगत 2007 के चुनावों से अधिक मत प्राप्त कर सत्ता में लौटेगी।

इस बैठक में भाजपा राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) श्री रामलाल, हिमाचल सह-प्रभारी तथा राष्ट्रीय सचिव श्री श्याम जाजू और प्रदेश महासचिव (संगठन) श्री पवन राणा भी उपस्थित थे। सभी प्रत्याशियों ने एक प्रपत्र भर कर विस्तृत रूप से अपना-अपना आकलन प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने मतदान केन्द्रों की कुल संख्या तथा उन बूथों पर जहां भाजपा को बढ़त मिल सकती है एवं अन्तिम निष्कर्ष जैसे विवरण दिए। बैठक के बाद, मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल का कहना था कि भाजपा को आराम से दो-तिहाई बहुमत प्राप्त हो जाएगा।

श्री धूमल ने कहा कि कुछ प्रत्याशियों ने माना कि संघर्ष कड़ा था और संभव है कि विजयी होने का अंतर कुछेक वोटों से ही हो। उन्होंने कहा कि किसी ने भी किसी पार्टीजन द्वारा विशेष रूप से गुप्त रूप से तोड़-फोड़ की शिकायत नहीं की, परन्तु यदि ऐसा कोई आरोप मिलता है कि उसे अनुशासन समिति को विचारार्थ भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा गुजरात में मतदान की तारीखों को पहले कराए जाने या हिमाचल प्रदेश में पहले मतगणना कराए जाने की मांग कर सकती थी, परन्तु हमने चुनाव कार्यक्रम को यथावत स्वीकार कर चुनाव आयोग का सम्मान किया।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि बैठक में संगठनात्मक चुनावों के लिए सदस्यता अभियान की प्रगति का अन्दाजा लिया गया और सदस्यता अभियान को फिर से आरम्भ करने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई जो विधानसभा चुनाव के कारण रूक गई थी। ■

बिना पतवार की नाव है यूपीए सरकार

✍ डॉ. मुरली मनोहर जोशी

यूपीए शासन में देश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति संसद के समक्ष एक बड़ा प्रश्न रही है और 22 नवंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में भी यह सवाल यक्ष प्रश्न बन कर खड़ा होगा। आज वित्तीय घाटा लगातार बढ़ रहा है और राजस्व प्राप्ति की जो उम्मीद थी, वह पूरी नहीं हो पा रही है। प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष करों की आवक कम हुई है और रुपये का अवमूल्यन होता जा रहा है। करंट अकाउंट घाटा बढ़ता जा रहा है। विकास की सारी योजनाएं ठप पड़ गई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाओं पर कोई काम नहीं हो रहा है। इन सारे हालात से निपटने के लिए सरकार के पास कोई कारगर और विश्वसनीय उपाय नहीं है। सरकार इन सबके निराकरण के लिए एक ही उपाय देश के सामने रख रही है, वह है- मल्टि-ब्रांड खुदरा बाजार में विदेशी निवेश को आमंत्रित करना।

सरकार संसद और कैग दोनों का अवमूल्यन कर रही है जो लोकतंत्र के लिए संकट है। इस सरकार के पास बहुमत तो है नहीं और बगैर जनादेश के वह किस प्रकार बैसाखियों पर खड़ी है, इसे सरकार इस सत्र के आइने में देख लेगी। कुल मिलाकर सरकार बिना पतवार की नाव की तरह समस्याओं के तूफान में दिशाहीन बनी हुई है।

हर मर्ज की दवा

सरकार एफडीआई को हर मर्ज की दवा बना कर पेश कर रही है। लेकिन इससे किसान, छोटे व्यापारी, लघु एवं मध्यम उद्योग आदि सभी बुरी तरह प्रभावित होंगे और बेरोजगारी बढ़ेगी। स्मरणीय है कि वर्तमान राष्ट्रपति एवं तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने लोकसभा में एवं आनंद शर्मा, वाणिज्य मंत्री ने राज्य सभा में यह आश्वासन दिया था कि सभी भागीदारों, जिसमें संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले सभी राजनैतिक दल, राज्य सरकारें शामिल हैं, की आम सहमति के बिना मल्टी-ब्रांड खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार की वादाखिलाफी विश्वास का गहरा संकट पैदा कर रही है। देश में इस नीति का कितना विरोध हो रहा है, यह समझने के लिए सरकार तैयार नहीं है। अब संसद में भी सरकार अपने इस फैसले के लिए कटघरे में खड़ी दिखाई देगी। इस मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव तक लाने की बात कर रही है। वह तो सत्र शुरू होने के बाद ही पता लगेगा कि विरोधी पार्टियां सरकार को घेरने के लिए क्या रणनीति अपनाती हैं।

संसद चलाना सरकार का दायित्व है और वह अपने इस दायित्व में पिछली बार बुरी तरह से फेल हुई थी और इस बार भी उसकी नीतियों के लिए विपक्षी पार्टियां उसे बख्शने को तैयार दिखाई नहीं देतीं। सबसे बड़ा मुद्दा तो यह आएगा कि सरकार के पास ऐसा कौन सा जादू का पिटारा है, जिससे देश के बिगड़ते आर्थिक हालात को वह ठीक कर देगी?

भ्रष्टाचार का मुद्दा

संसद के समक्ष विचारणीय मुद्दों में से एक बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का होगा। पिछला सारा सत्र इसी मुद्दे की भेंट चढ़ गया था। विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार देशव्यापी बन गया है। जिस बड़ी विदेशी पूंजी को सरकार खुदरा बाजार में लाना चाहती है, वह भ्रष्टाचार के सहारे ही आगे बढ़ती है। वालमार्ट ने स्पष्ट किया था कि नेताओं और अधिकारियों को अपने पक्ष में लाने के लिए लॉबिंग में उसने 5.3 करोड़ डॉलर खर्च किए थे। यह मुद्दा संसद में इस बार जोरशोर से उठेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार जो फैसले ले रही है, वे कहां लिए जा रहे हैं? उन्हें कौन ले रहा है? इतना ही नहीं, सरकार को यह जवाब देना होगा कि ये फैसले अभी क्यों लिए गए जब अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होना था। सरकार को जवाब देना होगा कि जिन रास्तों से अमेरिका और यूरोप सुधार नहीं ला सके उनसे यह सरकार कैसे अर्थव्यवस्था सुधार देगी?

एफडीआई के साथ पेट्रोल व रसोई गैस के दामों में वृद्धि और घरेलू रसोई गैस के सिलिंडरों का मुद्दा भी उठेगा। इन फैसलों से साफ हो गया है कि इस सरकार के पास मूल नीति का अभाव है। कभी यह सरकार गैस के दाम बढ़ा देती है, फिर घटा देती है। वह देश को यह समझाने में पूरी तरह से असफल है कि दाम क्यों बढ़ने चाहिए या क्यों घटने चाहिए। सरकार के कामकाज में एकरूपता नहीं है। पता ही नहीं चलता कि कौन क्या कर रहा है। आज शिक्षा के क्षेत्र में बदहवासी दिखाई दे रही है।

शिक्षा का व्यावसायीकरण किया जा रहा है। गरीब आदमी के बच्चों का भविष्य अंधकारमय है। सरकार महिलाओं और दलितों के हो रहे शोषण को काबू नहीं कर पा रही है। सरकार ने तेलंगाना को लेकर वादा किया था पर अभी तक उसे लेकर घोषणा नहीं की गई है। फिर देश की सुरक्षा के सवाल भी संसद में उठेंगे। चीन की गतिविधियां और पाकिस्तान की मार्फत घुसपैठ में हुई वृद्धि भी संसद को बेचैन करेगी। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान कम्बोडिया में चीन के प्रधानमंत्री से मिले हैं, तो संसद जानना चाहेगी कि प्रधानमंत्री ने चीन के साथ देश की चिंताओं को कैसे रखा है और उसका क्या परिणाम निकलने वाला है। इन सबके बीच सरकार की विदेश नीति को लेकर भी सवाल उठेंगे। सरकार से सवाल होंगे कि उसमें अस्पष्टता क्यों है? विभिन्न राष्ट्रों, खासतौर पर पड़ोसी देशों के साथ भारत की क्या नीति है, यह भी प्रश्न उठेगा।

कैग पर हमला

संसद के इस सत्र में यह साफ हो जाएगा कि सरकार किस प्रकार अपनी कमजोरियां छिपाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं का अवमूल्यन कर रही है। सरकार को अपना कामकाज ठीक करना चाहिए, लेकिन वह अपना कामकाज ठीक करने की बजाय कैग पर हमला कर रही है। सरकार को यदि लगता है कि कैग ने कुछ गलत किया है तो उसे इम्पीच करना चाहिए, न कि उस पर हमला कर उसका अवमूल्यन करना चाहिए। सरकार संसद और कैग दोनों का अवमूल्यन कर रही है जो लोकतंत्र के लिए संकट है। इस सरकार के पास बहुमत तो है नहीं और बगैर जनादेश के वह किस प्रकार बैसाखियों पर खड़ी है, इसे सरकार इस सत्र के आइने में देख लेगी। कुल मिलाकर सरकार बिना पतवार की नाव की तरह समस्याओं के तूफान में दिशाहीन बनी हुई है। ■

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं)

और कितनी किरकिरी

समाचार-पत्र अमर उजाला (21 नवम्बर 2012) में प्रकाशित संपादकीय टिप्पणी

मनमोहन सिंह सरकार ने 2 जी स्पेक्ट्रम नीलामी के मामले में शुरू से अब तक जो रवैया अख्तियार किया है, वह क्षुब्ध तो करता ही है, दूरसंचार जैसे एक बेहद महत्वपूर्ण मामले में उसकी नीतिगत विफलता और मनमानेपन का भी सुबूत देता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आवंटन रद्द किए जाने के बाद हाल में हुई 2 जी स्पेक्ट्रम की दोबारा नीलामी में लक्ष्य से कम राजस्व की प्राप्ति से बौखलाई सरकार अब दोबारा कैग पर हमलावर है कि उसके कपोल-कल्पित घाटे के आकलन के कारण दूरसंचार क्षेत्र की छवि खराब हुई है, जबकि सीबीआई की विशेष अदालत में पूर्व वित्त सचिव डी सुब्बाराव ने, जो इस समय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, जो कुछ कहा है, उससे शीशे की तरह साफ है कि 2 जी स्पेक्ट्रम आवंटन के समय अहम मुद्दे पर वित्त और दूरसंचार मंत्रालय के बीच तालमेल नहीं था।

> ***सरकार यह बात आखिर समझती क्यों नहीं कि 2 जी स्पेक्ट्रम मामले में कभी कैग, तो कभी सर्वोच्च न्यायालय के बार-बार निशाने पर आने से उसी की छवि खराब हो रही है।***

तब खुद सुब्बाराव ने 2001 की दर पर स्पेक्ट्रम आवंटित करने के दूरसंचार मंत्रालय के फैसले पर सवाल उठाया था। मानो पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा के समय में की गई गलतियां ही काफी न हों, पिछले दिनों 2 जी स्पेक्ट्रम की दोबारा नीलामी से संबंधित पूरी सूचनाएं भी सरकार ने शीर्ष अदालत को नहीं दीं, जबकि उसके द्वारा 122 लाइसेंस रद्द करने के कारण ही यह नीलामी हुई।

इस मामले में अदालती सक्रियता पर सवाल उठाने का औचित्य इसलिए नहीं है कि 2 जी स्पेक्ट्रम आवंटन में घोटाला सामने आने और शीर्ष अदालत के सक्रिय होने के बाद इससे जुड़ा कोई भी फैसला उसे संज्ञान में रखकर ही किया जाना है। सर्वोच्च न्यायालय की नाराजगी दरअसल इस बात को लेकर है कि सरकार ने पूरे लाइसेंस की नीलामी तो नहीं ही की, उसकी जानकारी भी उसे नहीं दी। उदाहरण के लिए, अदालत को यह बताया ही नहीं गया कि 800 और 1,800 मेगाहर्ट्ज की नीलामी की जाएगी, 900 मेगाहर्ट्ज की नहीं। उसे यह भी पता नहीं था कि 0.1 प्रतिशत स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं होगी। इस पूरे मामले को हलके में लेने का इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा कि सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दूरसंचार मंत्रालय के अनुसचिव (अंडर सेक्रेटरी) ने दाखिल किया, जबकि शीर्ष अदालत पहले ही यह स्पष्ट कर चुकी थी कि सचिव स्तर के अधिकारी का शपथपत्र ही स्वीकार किया जाएगा। सरकार यह बात आखिर समझती क्यों नहीं कि 2 जी स्पेक्ट्रम मामले में कभी कैग, तो कभी सर्वोच्च न्यायालय के बार-बार निशाने पर आने से उसी की छवि खराब हो रही है। ■

शासक ऐसा होना चाहिए

वीरेन्द्र सिंह परिहार

गत 19 अक्तूबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी भोपाल में जल संसाधन विभाग का उत्कृष्टता पुरस्कार वितरित किए। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सिर्फ अधिकारियों को ही पुरस्कृत नहीं किया, बल्कि कर्मचारियों, अमीनों, दैनिक वेतन-भोगियों यहां तक कि चौकीदारों को भी पुरस्कृत किया। इस तरह से मुख्यमंत्री द्वारा कुल 307 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया।

इसमें 10 राज्यस्तरीय, 42 कछार स्तरीय, 255 परियोजना मैदान स्तरीय लोग थे। तीनों पुरस्कार क्रमश: 50 हजार, 25 हजार और 10 हजार रुपयों के थे, जो सीधे पुरस्कृतों के बैंक-खातों में भेजे गए। मुख्यमंत्री ने सिर्फ इन लोगों को पुरस्कृत ही नहीं किया, बल्कि पुरस्कृत चौकीदारों, अमीनों और टाइमकीपरों को गले भी लगाया। अब सवाल यह कि जो सिंचाई विभाग कभी भ्रष्टाचार के मामलों में सबसे ज्यादा बदनाम विभाग थे, उनमें एक था। उस सिंचाई विभाग में आखिर ऐसा कौन-सा चमत्कार हो गया कि इस विभाग के अधिकार, कर्मचारी प्रशंसा के, पुरस्कार के, अभिनंदन के पात्र हो गए। अब यह किसे पता नहीं कि पूरे देश में जब कृषि की विकास दर दो प्रतिशत है, वहीं म.प्र. में वह 18 प्रतिशत है। ऐसी स्थिति में जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की कृषि विकास दर के चलते यूरोप तथा अमेरिका तक हैरत में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मप्र जल संसाधन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की अभूतपूर्व लगन और साहस के चलते यह हुआ। वर्ष 2011-12 में 16 लाख हेक्टेयर की सिंचाई की गई जो एक कीर्तिमान है। जिसके चलते मप्र में सचमुच हरित क्रांति हो चुकी है और गेहूं उत्पादन में वह पंजाब एवं हरियाणा के पश्चात तीसरा राज्य बन गया है। वर्ष 2012-13 में लक्ष्य यद्यपि 21 लाख हेक्टेयर सिंचाई का है, पर मुख्यमंत्री को विश्वास है कि हम 25 लाख हेक्टेयर खेतों में सिंचाई करेंगे। सच्चाई यह है कि मप्र में सिंचाई के क्षेत्र में यह क्रांति शिवराज सिंह की अगुवाई में जो हो रही है, उसमें नवाचारों का बहुत योगदान है। जैसे निर्माण कार्यों के लिए ई-टेंडरिंग, बांधों में जल-भराव की स्थिति जानने के लिए एसएमएस अलर्ट व्यवस्था, प्रति सप्ताह वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मैदानी कार्यों की जानकारी आदि। नई सिंचाई योजनाओं के प्रस्तावों पर त्वरित कार्यवाही कर उन्हें क्रियान्वयन के स्तर पर लाया गया। मुख्यमंत्री प्रदेश के प्रत्येक किसान के खेत तक पानी पहुंचाने को प्रतिबद्ध है। वस्तुत: शिवराज सिंह चौहान ने कृषि प्रधान देश के मर्म को महसूस किया है, और वह इस तरह से सिंचाई सुविधा और अन्य उपायों से किसानी को लाभ का धंधा बनाने की दिशा में सार्थक प्रयास कर रहे हैं। नि:संदेह यह उपलब्धि शिवराज सिंह के सुशासन का एक नमूना है। महात्मा गांधी का कहना था कि देश के छोटे से छोटे व्यक्ति को यह एहसास होना चाहिए कि स्वतंत्र भारत में देश को चलाने और बनाने में उसकी भी भागीदारी है। शिवराज सिंह ने गांधी की इस भावना को जीवंत ही नहीं किया है, बल्कि एक समता और समरसता युक्त समाज बनाने की दिशा में कदम भी बढ़ाया है। तभी तो वह समाज के सबसे निचले छोर पर खड़े दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को स्थायी सेवा में वर्गीकरण हेतु कदम उठाने जा रहे हैं। ■

मुख्यमंत्री द्वारा कुल 307 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया। इसमें 10 राज्यस्तरीय, 42 कछार स्तरीय, 255 परियोजना मैदान स्तरीय लोग थे। तीनों पुरस्कार क्रमश: 50 हजार, 25 हजार और 10 हजार रुपयों के थे, जो सीधे पुरस्कृतों के बैंक-खातों में भेजे गए। मुख्यमंत्री ने सिर्फ इन लोगों को पुरस्कृत ही नहीं किया, बल्कि पुरस्कृत चौकीदारों, अमीनों और टाइमकीपरों को गले भी लगाया। अब सवाल यह कि जो सिंचाई विभाग कभी भ्रष्टाचार के मामलों में सबसे ज्यादा बदनाम विभाग थे, उनमें एक था। उस सिंचाई विभाग में आखिर ऐसा कौन-सा चमत्कार हो गया कि इस विभाग के अधिकार, कर्मचारी प्रशंसा के, पुरस्कार के, अभिनंदन के पात्र हो गए।

छत्तीसगढ़ ने शुरू किया देश का पहला 'नगर सुराज' अभियान

शहरी क्षेत्रों में समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर शासन, प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को एक साथ जनता के बीच पहुंचाने के लिए देश का पहला 'नगर सुराज' अभियान शुरू करने का श्रेय छत्तीसगढ़ को मिला है, जहां मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में 19 नवम्बर को राजधानी रायपुर सहित

प्रदेश के सभी जिलों के 168 शहरों में यह अभियान आज से प्रारंभ हो गया। सप्ताहव्यापी अभियान के प्रति आज इन सभी शहरों में जनता ने भरपूर उत्साह दिखाया। हजारों की संख्या में नागरिक विभिन्न वार्डों में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविरों में शामिल हुए।

उल्लेखनीय है कि यह अभियान दो चरणों में इस महीने की 26 तारीख तक चलेगा। अभियान के तहत प्रदेश के दस नगर निगम क्षेत्रों, 32 नगर पालिकाओं और 126 नगर पंचायतों के तीन हजार से ज्यादा वार्डों में मंत्रियों, संसदीय सचिवों, सांसदों, विधायकों, नगरीय निकायों के महापौरों एवं अध्यक्षों और पार्षदों सहित सरकारी अधिकारी और कर्मचारी वार्ड स्तर पर शिविरों में जनता की समस्याओं को सुनने और यथा संभव उनके त्वरित निराकरण की पहल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में आज से प्रारंभ नगर सुराज अभियान हमारे ग्राम सुराज अभियान की तरह पूरे देश के शहरी क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों के लिए एक मॉडल अभियान साबित होगा। ग्राम सुराज अभियान की तर्ज पर नगर सुराज अभियान के लिए भी सरकारी कर्मचारियों के सुराज दलों का गठन किया गया है।

मुख्यमंत्री ने राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र के लखोली और मोतीपुर वार्ड में अभियान का शुभारंभ किया, जहां उन्होंने तीन हजार से ज्यादा मजदूरों को श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत सामग्री आदि का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर लखोली वार्ड में 17 करोड़ 41 लाख रूपए के 42 विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन और एक करोड़ 40 लाख रूपए के पांच नवनिर्मित कार्यों का लोकार्पण किया जिनमें एक करोड़ दस लाख रूपए की लागत से पुरानी गंज मंडी में निर्मित व्यावसायिक परिसर (शॉपिंग काम्पलेक्स) भी शामिल है। स्वास्थ्य और नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अमर अग्रवाल, लोक सभा सांसद श्री मधुसूदन यादव तथा नगर निगम महापौर श्री नरेश डाकलिया सहित प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव श्री सुनील कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उनके साथ थे।

इसी कड़ी में राजधानी रायपुर आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री राजेश मूणत नगर निगम के दो वार्डों - शहीद चुड़ामणी वार्ड और स्वामी आत्मानन्द वार्ड में आयोजित शिविरों में चौपाल लगायी और जनसमस्याओं का निराकरण करते हुए लगभग पौने चार करोड़ रूपए के विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। स्कूल शिक्षा और लोक निर्माण मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने अभियान के प्रथम दिवस पर आज यहां निगम क्षेत्र के तीन वार्डों - शहीद पंकज विक्रम वार्ड, सुधीर मुखर्जी वार्ड और इंदिरा गांधी वार्ड में लगभग पांच करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। उन्होंने इंदिरा गांधी वार्ड के लायंस क्लब, निवेदिता स्कूल, स्टेशन रोड में आयोजित शिविर में तेलघानी नाका से रेल्वे स्टेशन तक सड़क निर्माण के लिए 40 लाख रूपए की धनराशि तत्काल मंजूर कर दी। कृषि और श्रम मंत्री श्री चन्द्रशेखर साहू ने अभियान के प्रथम दिवस पर अभनपुर और नयापारा के शहरी वार्डों का दौरा किया।

विधानसभा अध्यक्ष श्री धरम लाल कौशिक ने बिलासपुर जिले के सिरगिट्टी नगर पंचायत क्षेत्र में नगर सुराज अभियान का शुभारंभ किया। ■

कांग्रेस का शासन विश्वासघातों और टूटे वायदों का युग : वेंकैया नायडू

भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री एम. वेंकैया नायडू, ने यूपीए सरकार के शासन में फैले भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ 21 नवम्बर को धरना देकर राष्ट्रव्यापी विरोध प्रगट किया। इस अवसर पर दिए गए उनके भाषण के प्रमुख बिन्दु प्रस्तुत हैं:

कांग्रेस का शासन विश्वासघात और वायदा भंग के युग को मुखरित करता है।

सरकार है जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है। आसमान छूती महंगाई आम आदमी की कमर को निरंतर तोड़ने में जुटी हुई है। किसानों की आत्महत्याएं भी निरंतर होती जा रही हैं। आंतरिक सुरक्षा की तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

समाज का हर वर्ग आज की सरकार से नाखुश है।

यह सरकार वायदा कुछ करती है और उसका आचरण ठीक उसके विपरीत रहता है।

- इस सरकार ने सत्ता में आते ही 100 दिन में महंगाई पर काबू पाने का वायदा किया था। अब इस सरकार ने स्वयं ही डीजल, एलपीजी जैसे पैट्रोलियम पदार्थों और उर्वरकों की कीमतों में ही 21 महीने के अंदर 12 गुणा वृद्धि कर डाली है।
- सरकार का वायदा था कि वह विदेशों ने कालाधन को वापस लाने के लिए कदम उठाएगी। अब, वह फ्रांस से मोटे तौर पर 700 लोगों के नाम मिलने के बाद भी उनका

संरक्षण करने में जुटी है।

- आम आदमी के कल्याण पर ध्यान देने की बजाए यह सरकार बेलगाम महंगाई बढ़ाने में लगी हुई है।

सरकार ने भुला दिया किसानों को : निर्यात नीति के प्रति लापरवाही से किसानों के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

किसानों को अपने अनाज का भण्डारण करने के लिए स्थान नहीं मिल रहा है, जिसके कारण लाखों टन अनाज सड़ जाता है। इस सरकार ने झूठे वायदे कर तेलंगाना के लोगों के साथ धोखा किया है और आंध्र प्रदेश के पूरे राज्य को अपनी अनिर्णयता के कारण हंगामे की स्थिति में डाल दिया है। सरकार 1990 जैसी स्थिति की बात करती है। परन्तु इसके लिए जिम्मेदार कौन है?, इसका कारण और कुछ नहीं, सरकार की अर्थव्यवस्था की बदइंतजामी है।

सरकार का वायदा था कि वह तेजी से अर्थव्यवस्था का विकास करेगी और अधिक समावेशी वृद्धि, राजकोषीय बुद्धिमत्ता एवं कम मुद्रास्फीति की अर्थव्यवस्था खड़ी करेगी। परन्तु वास्तविकता क्या है?

- मुद्रास्फीति दो-अंकों तक पहुंच गई है।
- विकास दर एक दशक में सबसे कम गति से लगभग 5.5 प्रतिशत तक रह गई है।
- प्रधानमंत्री स्वयं ही विकास ह्रास और गिरते निर्यात पर चिंता जता रहे हैं।
- केन्द्र और राज्यों के संयुक्त रूप से राजकोषीय घाटा सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच कर विश्व में तीसरे स्थान पर आ गया है।
- विश्व के लगभग सभी देशों में मुद्रास्फीति की स्थिति कहीं अधिक ऊंची है।
- चालू खाता घाटा जीडीपी का 3.8 प्रतिशत दिखाया गया है जो दूसरे नम्बर पर सबसे ऊंचा है।

जैसा कि लोग कहते हैं कि राजकोषीय घाटा, व्यापार घाटा और मुद्रास्फीति का स्तर किसी भी व्यक्ति की नाडी दर, रक्तचाप दबाव और तापमान की व्यवस्था के समान होता है। ये सभी सामान्य से कहीं अधिक है।

सरकार ने महिला आरक्षण का प्रावधान न कर उनका अपमान किया है। इस सरकार का कहना है कि 10वीं लोकसभा के चुनाव महिलाओं के 1/3 आरक्षण के आधार पर किए जाएंगे। परन्तु ऐसी स्थिति अभी तक कहीं नजर

नहीं आती है।

सरकार ने संसद के साथ भी छल किया है। उसने इस गरिमामयी संस्था को आश्वासन दिया था और यह सरकार निर्लज्जतापूर्वक विपरीत आचरण कर रही है। एक तरफ यह सरकार वायदे तोड़ती है तो दूसरी तरफ एक तरफा ढंग से ऐसे मुद्दों पर कदम उठाती है जिस पर यह सरकार विपक्ष में रहते हुए कभी विरोधी किया करते थे। इसी सरकार ने विपक्ष में रहते हुए खुदरा बाजार में एफडीआई का विरोध किया था, अब यही सरकार खुदरा बाजार में एफडीआई की जबरदस्त हिमायत करने लग रही है।

यह वह सरकार है जो सत्ता से बाहर होने पर कुछ और बातों की समर्थक रहती है तो सत्ता में आते ही ठीक उसका विपरीत आचरण होता है। जब यह सरकार विपक्ष में थी तो इसने संसद में बार बार व्यवधान डाला था, आज वही सत्ता में आते ही विपक्ष को संसद की शुचिता का पाठ पढ़ाने में जुटी है।

यह सभी मोर्चों पर विफल रही है। यह साढ़े आठ सालों तक नींद में सोती रही और इन सभी वर्षों में नीति अपंगुता की स्थिति बना दी। अब अचानक ही यह भावोन्मत्त बन गई है। अपने भारी घोटालों को छुपाने की खातिर उसने तथाकथित सुधारों की बातें कहनी शुरू कर दी हैं जो जन विरोधी हैं।

इस सरकार ने हर संस्था (इंस्टीट्यूशन) का ह्रास, बदनाम और दुरूपयोग किया है जिसमें सीएजी, ईसी, सीवीसी, राज्यपाल संस्था, सीबीआई आदि सभी संवैधानिक और विधि सम्मत संस्थाएं शामिल हैं। इसने सीईसी की अथारिटी को कमजोर करने के लिए ई. सी. (चुनाव आयोग) का विस्तार किया और अपने लोगों को नियुक्त किया। अब वह सीएजी पर प्रहार कर रही है और बदनाम कर रही है। इसने सीवीसी पद पर दागी व्यक्ति को नियुक्त करने की कोशिश की।

इस सरकार के पास अब घोटालों की अनगिनत संख्या है। इसे आप में जहां कहीं भी गलती दिखाई पड़ती है उसे यह सरकार काले रंग से पोतना चाहती है। परन्तु सीएजी को काले रंग से पोतने से घोटाले खत्म नहीं हो सकते हैं। कांग्रेस भूल गई है कि जब इसने 1989 में सीएजी को बदनाम किया था तो लोगों ने उसे मात दी थी। अब जब कभी भी चुनाव होंगे तो यही बात फिर से दोहराई जाएगी।

इस सरकार के पास अब घोटालों की अनगिनत संख्या है। इसे आप में जहां कहीं भी गलती दिखाई पड़ती है उसे यह सरकार काले रंग से पोतना चाहती है। परन्तु सीएजी को काले रंग से पोतने से घोटाले खत्म नहीं हो सकते हैं। कांग्रेस भूल गई है कि जब इसने 1989 में सीएजी को बदनाम किया था तो लोगों ने उसे मात दी थी। अब जब कभी भी चुनाव होंगे तो यही बात फिर से दोहराई जाएगी।

यह सरकार इस बात के लिए बुरी तरह से बदनाम है कि वह सीबीआई का दुरूपयोग करती है, राजनैतिक विरोधियों को मुसीबत में डालती है, 30 तटस्थ दलों को काबू करने में लग जाती है, जो इसकी विचारधारा के साथ नहीं चलते हैं और अपने सहयोगी दलों को नियंत्रण में रखती है जिसके लिए यह सीबीआई को अपना सर्वश्रेष्ठ आज्ञाकारी बना कर रखती हैं।

यह सरकार जानती ही नहीं है कि गठबंधन धर्म किस चिड़िया का नाम है। वह जानती ही नहीं है कि गठबंधन किस प्रकार चलाया जाता है क्योंकि उनके सहयोगी दल यही कहते रहते हैं कि हम से परामर्श किया ही नहीं गया। वह सदैव एकतरफा निर्णय लेती है और सार्वजनिक रूप से एफडीआई निर्णय का विरोध करती है। इसने ऐसे लोगों को पदोन्नति दी जिन पर गम्भीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। उनकी नीति है- भ्रष्ट को पदोन्नत करो ईमानदार को पदावन्त करो। इसकी बजाय किस सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को दण्डित करने की कोशिश करे, वह सरकार में भ्रष्ट लोगों का संरक्षण और पदोन्नत करने का प्रयास करती है और जांच को विफल बनाने की कोशिश करती है।

भाजपा अध्यक्ष के खिलाफ एक आरोप लगाया गया। उन्होंने किसी भी जांच का सामना करने के लिए इच्छा प्रगट की। दूसरी तरफ, कांग्रेसी नेतृत्व न केवल मीडिया से बचती है बल्कि उसके खिलाफ लगे गम्भीर आरोपों की जांच का आदेश भी नहीं देती है। भाजपा और कांग्रेस में यही अन्तर है।

कांग्रेस में सरकार में बने रहने का कोई नैतिक या राजनैतिक अधिकार नहीं रह गया है। वह देश पर बोझ बन गई है। उसका तो बोरिया बिस्तरा बंद हो जाना चाहिए और सत्ता से बाहर हो जाना चाहिए। और यह जितनी जल्दी हो, उतना ही देश का भला है।

हम निरंतर इस सरकार के खिलाफ संसद के अंदर और बाहर राजनैतिक संघर्ष करते रहेंगे।

आगामी चुनावों में भ्रष्टाचार, महंगाई, मुद्रास्फीति, खुदरा बाजार में मल्टी-ब्रांड एफडीआई, कृषि संकट, किसानों की पीड़ा और टूटे वायदे प्रमुख मुद्दे होंगे। और लोगों के सामने भाजपानीत एनडीए ही एकमात्र विकल्प रहेगा। ■

बाल ठाकरे नहीं रहे

गत 17 नवम्बर 2012 को शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे का बांद्रा (मुंबई) स्थित उनके आवास 'मातोश्री' में निधन हो गया। वे 86 वर्ष के थे। उनके निधन की घोषणा से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई।

23 जनवरी 1926 को पूणे, तत्कालीन बांबे रेजीडेंसी में मराठी परिवार में पैदा हुए बाल श्री ठाकरे के पिता श्री केशव सीताराम ठाकरे सामाजिक कार्यकर्ता और जाने-माने लेखक थे।

श्री बाल ठाकरे ने 19 जून 1966 को शिवसेना राजनीतिक दल की स्थापना की। 1989 में पार्टी के मुखपत्र सामना की शुरूआत की। इसके संपादकीय में वह चर्चित विषयों पर अपने तीखे विचार रखते थे। श्री ठाकरे ने 46 साल तक शिवसेना को करिश्माई नेतृत्व दिया। कभी चुनाव नहीं लड़ा, न ही कोई शासकीय पद संभाला, इसके बावजूद बाला साहेब ने जिंदगीभर महाराष्ट्र की जनता के दिलों पर राज किया।

एक बार कोई वक्तव्य देकर उससे पीछे न हटने वाले श्री ठाकरे अपने वक्तव्य के लिए काफी मशहूर थे। उनके वक्तव्य का पूरे महाराष्ट्र में गहरा प्रभाव पड़ता था। श्री ठाकरे की सांगठनिक क्षमता और वक्तृत्व शैली की ही विशेषता थी कि 1966 से लगातार 45 वर्ष तक दशहरे के दिन दादर के शिवाजी पार्क में बगैर बुलाए लाखों शिवसैनिक अपने नेता को सुनने जमा हो जाते थे। अनेक राष्ट्रीय मुद्दों पर राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से विचार करना और उस पर पहल करना उनकी विशेषता थी। देश की प्रमुख चुनौती बांग्लादेशी घुसपैठ के विरोध में उन्होंने आवाज बुलंद की तो रामजन्मभूमि आंदोलन में भी उनकी पार्टी ने बढ़-चढ़कर भाग लिया।

स्थानीय समस्याओं को सुलझाने में शिवसेना ने उल्लेखनीय काम किया ही इसके साथ आतंकवादियों को महाराष्ट्र ही नहीं अपितु भारत से बाहर खदेड़कर और मिलों के शहर मुंबई में कम्युनिस्टों के हाथ से ट्रेड यूनियन छीनकर भूमिपुत्रों के हक का नारा बुलंद करके शिवसेना ने अपनी जड़ें मजबूत की। इस दल ने कालांतर में मुंबई के करीब सभी श्रमिक संगठनों पर कब्जा जमाया। बाद में भारतीय जनता पार्टी से इसका तालमेल हुआ। 1995 में दोनों दलों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा और विजय भी प्राप्त की। 1995 से लेकर 1999 तक सरकार चली। राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए परिवार को शोक संदेश भेजा है। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा कि ठाकरे के लिए महाराष्ट्र के हित खास तौर से महत्वपूर्ण थे और वह हमेशा इसकी जनता में गौरव की भावना पैदा करने के उत्सुक रहे। ■

शोक संदेश

श्री बाल ठाकरे के निधन पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने अपने शोक संदेश में कहा कि बाला साहब का निधन उनके लिए व्यक्तिगत क्षति है। उन्होंने कहा ''उनके दिल में जो रहता था, वही उनके जुबान पर होता था। उन्होंने अपने मन की बात कहने में कभी झिझक नहीं दिखाई। भाजपा और शिवसेना दोनों ने अपना सहारा खो दिया है।''

भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी ने कहा, ''एक असाधारण व्यक्ति और राजनीतिज्ञ चला गया। स्वतंत्र भारत के 65 वर्ष के दौरान देश पर ऐसी गहरी छाप शायद ही किसी ने छोड़ी होगी जैसी छाप बाल ठाकरे ने छोड़ी है।''

लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज ने कहा कि बाला साहब के निधन की खबर से मुझे गहरा सदमा हुआ है। एक शेर नहीं रहा।

गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि ठाकरे साहस और वीरता के प्रतीक थे। मैंने एक मार्गदर्शक शक्ति खो दी है। ■

'विराट व्यक्तित्व के धनी थे कैलाशजी'

संवाददाता द्वारा

गत 9 नवम्बर को पटना में भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं गुजरात व राजस्थान के पूर्व राज्यपाल श्री कैलाशपति मिश्र की श्रद्धांजलि सभा में भाजपा समेत विभिन्न दलों के नेताओं ने उन्हें विराट व्यक्तित्व का धनी बताते हुए कैलाश पर्वत की तरह दृढ़ संकल्पों वाला आदर्श महापुरूष कहा। विभिन्न दलों के नेता और कार्यकर्ता रवीन्द्र भवन में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में घंटों तक दिवंगत कैलाशपति मिश्रा को श्रद्धा सुमन अर्पित करते रहे।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने कहा कि कैलाश जी का संपूर्ण जीवन सेवा में लगा रहा। उन्होंने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। जन्म के साथ मृत्यु भी निश्चित है लेकिन कैलाश जी ने पूरा जीवन संगठन और समाज को समर्पित कर स्वयं को अमर बना दिया। कैलाश जी ऐसे कर्मयोगी थे जिन्होंने भक्तियोग से साधना की संपूर्ण जीवन राष्ट्र व समाज निर्माण में लगा दिया।

लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज ने कैलाशपति मिश्र को अजातशत्रु की संज्ञा दी। उनहोंने कहा कि कैलाश जी अन्य दलों में भी बहुत लोकप्रिय थे। वह एक आदर्श संगठनकर्ता और कुशल प्रशासक भी रहे।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह श्री सुरेश सोनी ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्होंने पूरा जीवन राष्ट्र और समाज की सेवा में गुजार दिया। वह हमेशा दृढ़ संकल्पों के साथ संगठन करने में जुटे रहे। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि

कैलाश जी ने पूरा जीवन संगठन और समाज को समर्पित कर स्वयं को अमर बना दिया। कैलाश जी ऐसे कर्मयोगी थे जिन्होंने भक्तियोग से साधना की संपूर्ण जीवन राष्ट्र व समाज निर्माण में लगा दिया।

दूसरे दलों के लोग भी मिश्र से मिलने के बाद भाजपा के प्रति अपनी निर्धारित धारणा बदलने पर विवश हो जाते थे। राज्य सभा में भाजपा संसदीय दल के उपनेता श्री रविशंकर प्रसाद ने मिश्र के कई संस्मरण सुनाए और कहा कि वह एक स्थितप्रज्ञ एवं महान आदर्श व्यक्ति थे। वह विजय के क्षणों में गंभीर और हार तथा विषम परिस्थितियों में मुस्कुराते नजर आते थे। उपमुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार भाजपा विधायकों की संख्या दो से 91 पर आ गई तो इसका सारा श्रेय कैलाश जी को जाता है। बिहार के इतिहास के हर पन्ने पर उनका हस्ताक्षर कायम रहेगा।

श्रद्धांजलि सभा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सर्वश्री डॉ. सीपी ठाकुर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांतीय संचालक शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री व हाजीपुर से जदयू सांसद रामसुंदर दास, राजद के शकुनी चौधरी, सीपीआई के बद्रीनारायण लाल, कांग्रेस के केदारनाथ पांडेय, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे तथा सांसद व अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा समेत विभिन्न दलों के नेताओं ने अपने विचार रखे और श्रद्धा निवेदित की। राजद के शकुनी चौधरी ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कैलाशपति मिश्र की आदमकद प्रतिमा विधानमंडल परिसर में लगाए जाने की आवाज उठाई। विदित हो कि कैलाशपति मिश्र का निधन तीन नवंबर को पटना में हो गया था। उनका जन्म 5 अक्टूबर 1923 को भोजपुर जिले के गांव में हुआ था। ■